नई दिल्ली
13
सितंबर, 2026
रविवार
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 164

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com
Email : timesofpedia@gmail.com

फिन एलन बीबीएल में बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी 07

पीएम मोदी का आह्वान: ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है, लेकिन डिसीजन में बैक रो में

नई दिल्ली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आधिकारिक आगाज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन संबोधन के साथ हुआ।

पीएम मोदी ने अपने भाषण में ग्लोबल साउथ के देशों की मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा, वे वैश्विक संकटों की अग्रिम पंक्ति में हैं, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में पीछे हैं। उन्होंने ब्रिक्स देशों से वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में ब्रिक्स प्रतिनिधियों का स्वागत कर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन-केंद्रित और मानवता-प्रथम दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता को भारत की प्राथमिकताएं बताया। इन प्राथमिकताओं के तहत 350 से अधिक बैठकों का आयोजन हुआ और करीब 30 शहरों में प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने भारत की अध्यक्षता को सफल बनाने में मिले सक्रिय सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के संस्थागत कामकाज में निरंतरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, भले ही इसकी अध्यक्षता हर साल बदलती है। उन्होंने एक ऐसा तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा जिसके तहत ट्रोइका व्यवस्था के जरिए सभी पहलों और नतीजों पर आगे की कार्रवाई हो सके। इसके साथ ही, उन्होंने हर फैसले से जुड़े नोडल पॉइंट, समय-सीमा और कार्यान्वयन की स्थिति को दर्ज करने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरी बनाने का सुझाव दिया। अपने संबोधन में, पीएम मोदी ने कहा कि हमें ब्रिक्स को मजबूत करते हुए वैश्विक सुधार की दिशा भी तय करनी होगी। उन्होंने मौजूदा वैश्विक शासन संरचना की तुलना एक पिरामिड से की, जिसके ऊपरी भाग में शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार केंद्रित है, जबकि निचले भाग में वे देश हैं जो इन निर्णयों से प्रभावित होते हैं लेकिन उन्हें आकार नहीं दे पाते।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है। इस स्थिति को बदलने के लिए, पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों से मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार करने का आह्वान किया, जिसे अगले शिखर सम्मेलन तक एक ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप का रूप दिया जा सके। इस रोडमैप को बनाने में तीन मुख्य पहलुओं झ्र प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम-निर्माण का ध्यान रखने की बात कही गई। प्रतिनिधित्व के संबंध में, पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को अब और टाला न जा सकने वाला मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर टेक्स्ट-आधारित बातचीत को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। इसी प्रकार, वित्तीय संस्थानों में मतदान शक्ति, नेतृत्व पदों और नीतिगत प्राथमिकताओं को आज की आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

जवाबदेही के तहत, उन्होंने वैश्विक संस्थानों में मानवता का विश्वास बनाए रखने के लिए समस्याओं का प्रभावी समाधान करने में उनकी क्षमता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने समुद्री नाविकों के लिए एक सी-फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा, जो संकटकालीन अलर्ट, चिकित्सा सहायता, परिवारों को सूचना और निकासी में सहयोग प्रदान करेगा। नियम-निर्माण के संबंध में, पीएम मोदी ने भविष्य के वैश्विक नियमों (जैसे एआई, साइबर स्पेस, आउटर स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी) को तय करने में समान भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों के युवा राजनयिकों और नीति निमार्ताओं को वार्ता कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण और कानूनी विशेषज्ञता प्रदान करके उन्हें नियम-ग्रहणकर्ता से नियम-निमार्ता बनाने के प्रयास करना होगा।

...ऐसा निर्णय लिया जाना विशेष महत्व रखता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज संयुक्त राष्ट्र दक्षिण-दक्षिण सहयोग दिवस है, और इस दिन ऐसा निर्णय लिया जाना विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि भारत में आयोजित इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का संदेश स्पष्ट होना चाहिए : यदि हमारा भविष्य साझा है, तब उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए।

भारत को मिलेगा किलर ड्रोन

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने मीडियम रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है, जिसमें 1,000 किलोमीटर से ज्यादा ऑपरेशनल रेंज और 9 घंटे से ज्यादा लोइटर टाइम की क्षमता मांगी गई है।

यह प्रणाली लंबे समय तक हवा में रहकर लक्ष्य पर नजर रख सकेगी और सटीक समय पर हमला कर पाएगी, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्तावित हथियार को युद्धपोतों के साथ-साथ जमीन से भी लॉन्च किया जा सकेगा और इसे कंटेनर में रखकर संचालित किया जाएगा। इसकी गति 75 नॉट से ज्यादा और परिचालन ऊंचाई 15,000 फीट तक होगी। सिस्टम में इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर वाला मॉड्यूलर सीकर लगा होगा, जो लक्ष्य की निगरानी और अंतिम चरण में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। खास बात यह है कि यह प्रणाली जीएनएसएस यानी सामान्य सैटेलाइट नेविगेशन उपलब्ध न होने पर भी स्वायत्त तरीके से काम करने में सक्षम होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाएगी।

एक मिशन कंट्रोल यूनिट एक साथ 10 म्यूनिशन तक संभाल सकेगी, और नियंत्रण को जहाज व जमीन पर मौजूद कंट्रोल स्टेशन के बीच भी बदला जा सकेगा। यह लोइटरिंग म्यूनिशन ब्रह्मोस जैसी महंगी क्रूज मिसाइलों का एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करेगा। यह हथियार किसी इलाके में घंटों मंडरा सकता है, लक्ष्य की स्थिति बदलने पर हमले को टाला जा सकता है और जरूरत पड़ने पर एक साथ कई प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

एक हजार किमी होगी रेंज, बढ़ेगी नौसेना की ताकत

हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों के मद्देनजर, 1,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाला यह समुद्र-आधारित सिस्टम भारत के लिए सामरिक रूप से अहम होगा। पाकिस्तान नौसेना द्वारा हाल ही में अपने मुदमैर लोइटरिंग म्यूनिशन के प्रदर्शन के बाद भारत के लिए ऐसा हथियार जरुरी हो जाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कई निजी और स्वदेशी कंपनियां लंबी दूरी के ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन पर काम कर रही हैं, जैसे न्यूस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज का शेषनाग-150। आरएफआई में बाय इंडियन-आईडीडीएम या बाय इंडियन श्रेणी के तहत खरीद का रास्ता रखा गया है, जिससे घरेलू रक्षा उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम केवल एक नए ड्रोन की खरीद नहीं, बल्कि समुद्री युद्ध की बदलती तस्वीर और भारत की दीर्घकालिक निगरानी व स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक गेमचेंजर साबित होगा।

संक्षिप्त वार्ता

जम्मू-कश्मीर के तीन जिलों में एनआईए ने 7 ठिकानों पर मारे छापे

श्रीनगर। एनआईए ने आतंकी साजिश की जांच के सिलसिले में कश्मीर रीजन के अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया कि कुलगाम, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में एजेंसी ने तलाशी अभियान चलाया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने कश्मीर में सात जगहों पर शनिवार सुबह तलाशी अभियान शुरू किया। कुलगाम जिले में दो, बांदीपोरा में तीन और बारामूला के सोपोर में 2 ठिकानों की तलाशी ली है।

सूत्रों ने कहा कि यह तलाशी सीमापार से रची गई कथित आतंकी साजिश की जांच का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर और स्थानीय ओवर ग्राउंड वर्कर शामिल थे। ओवर ग्राउंड वर्कर पर घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की मदद करने का शक है। सूत्रों के मुताबिक ये तलाशी जकूरा पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे से जुड़ी हैं, जिसे बाद में एनआईए ने फिर से रजिस्टर किया था। तलाशी अभियान में एनआईए की टीमों को स्थानीय पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की टीमें मौजूद रहीं।

उत्तराखंड में भारी बारिश से बैली ब्रिज बहा, छत्तीसगढ़ में तीन छात्र नदी में डूबे

नई दिल्ली। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच पिथौरागढ़ के कुलागाड़ नाले पर बना 170 फीट लंबा बैली ब्रिज बह गया। इससे चीन सीमा से लगी व्यास, दारमा और चौदांस घाटियों का संपर्क टूट गया। यह ब्रिज 27 अगस्त को ही बनाया गया था। पुराना पुल 18 अगस्त को चट्टान गिरने से टूट गया था।वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में हसदेव नदी के तेज बहाव में तीन कॉलेज छात्र बह गए। तीनों शुक्रवार को बिलासपुर के चौकसे कॉलेज के 8 छात्र-छात्राओं के साथ पिकनिक मनाने देवरी गांव गए थे। नदी किनारे सेल्फी लेने के दौरान एक छात्र का पैर फिसला, उसे बचाने के लिए कूदे 2 अन्य छात्र भी नदी में बह गए। तीनों की तलाश जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बाढ़ से 15 जिलों में 47 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यूपी के 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। चार लाख की आबादी प्रभावित है। 21 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कानपुर-उन्नाव में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। नदी के किनारे पर बने गांवों में 10 फीट तक पानी भर गया है।

भारत-चीन के बीच 6 साल बाद सीधी उड़ानें शुरू

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा लगभग छह साल के बाद फिर से शुरू हो गई है। चाइना सदर्न एयरलाइंस ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवाएं बहाल की हैं। यह खबर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आगमन से ठीक पहले सामने आई है, जहां वे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं। इस कदम को भारत और चीन के बीच सुधरते रिश्तों के एक महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 में शामिल होने के लिए भारत आ रहे शी जिनपिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है, जिसमें कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की संभावना है।

चाइना सदर्न एयरलाइंस ने 12 सितंबर 2026 को घोषणा की कि वह 21 सितंबर से ग्वांगझू-नई दिल्ली मार्ग पर नियमित यात्री उड़ानें फिर से शुरू करेगी। यह सेवा लगभग 6 साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू की जा रही है। एयरलाइन ने बताया कि सेवा बहाल होने के बाद वह दक्षिण एशिया में 8 राउंड-ट्रिप मार्गों पर हर सप्ताह 100 से अधिक उड़ानों का संचालन करेगी। चीन की विमानन कंपनियों की ओर से भारत के लिए सीधी उड़ानों की बहाली दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले अप्रैल में एयर चाइना ने बीजिंग-दिल्ली सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू की थी और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने 18 अप्रैल से कुनमिंग-कोलकाता के बीच सीधी उड़ानें दोबारा शुरू की थीं।

ब्रिक्स समिट: वैश्विक मंच पर बढ़ रहा है भारत का प्रभाव

नई दिल्ली। ब्रिक्स समूह वैश्विक मंच पर अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है, जिसका आकर्षण उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां पाकिस्तान इस प्रभावशाली समूह में शामिल होने के लिए लगातार प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर भारत की मेजबानी में हुए एक सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों ने वैश्विक व्यापार में मनमाने टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों को लेकर कड़ी चिंता व्यक्त की है।

पाकिस्तान लंबे समय से ब्रिक्स की सदस्यता पाने की कोशिश कर रहा है और उसने 2023 में औपचारिक आवेदन भी किया था। आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा पाकिस्तान अपने लिए नए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक रास्ते तलाश रहा है, खासकर न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थानों तक पहुंच बनाकर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर अपनी निर्भरता कम करने की उम्मीद में। हालांकि, ब्रिक्स में नए सदस्यों को शामिल करने का फैसला आम सहमति से होता है, और पाकिस्तान की सदस्यता की राह में भारत की सहमति एक बड़ी राजनीतिक अड़चन मानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी तनाव के कारण भारत की सहमति के बिना पाकिस्तान की सदस्यता मुश्किल दिखती है, भले ही उसे रूस और चीन जैसे देशों से समर्थन की उम्मीद हो। इसी बीच, ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने एकतरफा टैरिफ और व्यापार से जुड़े दूसरे प्रतिबंधों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। हालांकि, बयान में किसी देश या राष्ट्रपति का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन इसमें जिस तरह एकतरफा व्यापार और वित्तीय कदमों, ऊंचे टैरिफ और व्यापार बाधाओं का जिक्र किया गया है, उसे अमेरिका की मौजूदा व्यापार नीति, विशेषकर पूर्व राष्ट्रपति की नीतियों, के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। समूह के सदस्यों ने कहा कि ऐसे कदम वैश्विक व्यापार में गंभीर गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं हैं। ब्रिक्स देशों ने एक ऐसी वैश्विक व्यापार व्यवस्था का समर्थन किया है जो खुली, पारदर्शी, गैर-भेदभाव वाली और नियमों पर आधारित हो। उन्होंने भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक विभाजन, नीतिगत अनिश्चितता और बढ़ते कर्ज जैसी मौजूदा वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का भी उल्लेख किया, जिनका सबसे अधिक असर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। ब्रिक्स साफ तौर पर चाहता है कि दुनिया के देशों के बीच व्यापार के नियम सभी के लिए एक जैसे हों और कोई एक देश अपनी तरफ से ऐसे फैसले न ले, जिससे दूसरे देशों के कारोबार पर अचानक बड़ा असर पड़े।

अब आपकी जमीन का भी बनेगा आधार कार्ड: जमीन का पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा डिजिटल

नई दिल्ली। सरकार ने सभी के जमीन का रिकॉर्ड रखने के लिए नई स्कीम की शुरूआत की है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोर्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ग्रामीण से लेकर शहरी तक सभी जमीनों का रिकॉर्ड होगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोर्डनाइजेशन प्रोग्राम के तीसरे फेस की पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोर्डनाइजेशन प्रोग्राम 3.0 स्कीम के लिए 2026-31 के दौरान 565.5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य लैंड रिकॉर्ड, मैप, रजिस्ट्रेशन और संबंधित आंकड़ों को जीआईएस बेस्ड डिजिटल फ्रेमवर्क पर लाना है।

लॉन्च के दौरान केंद्रीय ग्रमीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह स्कीम व्यक्तिगत रिकॉर्ड के डिजिटलीजेशन से आगे बढकर एक यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम की ओर लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को संस्थागत लोन आसानी से प्राप्त करने में मदद मिलेगी और सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। चौहान ने कहा कि भूमि केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है। यह हमारे किसानों का गौरव है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और आने वाली पीढ़ियों की पहचान है।

जीआईएस-इनेबल्ड लैंड स्टैक

लैंड स्टैक एक यूनिफाइड डिजिटल फ्रेमवर्क है जो जियो-रेफरेंस्ड कैडस्ट्रल मैप, अधिकारों का रिकॉर्ड, संपत्ति पंजीकरण और संबंधित अदालती मामलों जैसे भूमि से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जीआईएस-आधारित डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से एक साथ लाएगा। यह भूमि से संबंधित अलग-अलग सिस्?टम को आपस में जोड़ने और इंटरऑपरेबल तरीके से एक्सेस करने में सक्षम बनाएगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोर्डनाइजेशन प्रोग्राम 3.0 के तहत, हर राज्य एपीआई के माध्यम से भूमि संबंधी डेटासेट और सिस्टम को एकसाथ करके अपना खुद का लैंड स्टैक डेवलप कर सकेगा। ये राज्य-स्तरीय स्टैक एक नेशलन लैंड स्टैक का आधार बनेंगे, जिससे संबंधित अधिकारियों के पास डेटा और कंट्रोल होगा।

यूनिवर्सल भू-आधार

इस स्कीम के तहत देश के हर जमीन को 14-अंकों का एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर दिया जाएगा, ताकि संपत्तियों की स्पष्ट पहचान की जा सके और धोखाधड़ी को खत्म किया जा सके।

रजिस्ट्रेशन सर्विस सेंटर में बदलाव

पासपोर्ट सेवा सेंटर्स की तर्ज पर ज्यादा भीड़-भाड़ वाले 75 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को डिजिटल और बेहतर सुविधाओं के साथ इसे सर्विस सेंटर्स के तौर पर आधुनिक बनाया जाएगा।

विरासत के अधिकारों की सुरक्षा और पुश्तैनी जमीन से जुड़े विवादों को कम करने के लिए, जमीन और संपत्ति के पुराने रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से स्कैन करके डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।

रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी

इन रजिस्टर्ड दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़ी देनदारियों या ऋण की जानकारी देने वाला एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो भूमि के स्वामित्व की जांच, पुराने खरीद-बिक्री के इतिहास और संपत्ति से जुड़ी आवश्यक जांच को आसान बनाएगा।

पेपरलेस रेवेन्यू कोर्ट्स

राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करके इसे सीधे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा, ताकि लंबित मामलों की संख्या घटाई जा सके और म्यूटेशन से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी लाई जा सके।

भारत के परमाणु जखीरे में बढ़ोतरी: एफएएस ने 190 हथियार होने का दावा

नई दिल्ली। अमेरिका की फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (एफएएस) के ताजा अनुमान के अनुसार, भारत के पास अब करीब 190 असेंबल किए गए परमाणु हथियार होने का दावा किया गया है, जो देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में लगातार मजबूती का संकेत है।

इसमें से 160 से अधिक हथियार सक्रिय डिलीवरी सिस्टम से जुड़े बताए गए हैं। हालांकि, भारत सरकार अपने परमाणु हथियारों की आधिकारिक संख्या सार्वजनिक नहीं करती, इसलिए एफएएस के ये आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं और वास्तविक संख्या भिन्न हो सकती है।

एफएएस सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन, सार्वजनिक स्रोतों, सैटेलाइट तस्वीरों और रणनीतिक सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर परमाणु हथियारों की संख्या का अनुमान लगाते हैं। विश्व की अधिकांश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अपनी सटीक परमाणु हथियार क्षमता को गोपनीय रखते हैं, जिससे इन आकलनों का उपयोग वैश्विक परमाणु रणनीति और सुरक्षा संबंधी चचाओं में किया जाता है।

तैयार हो सकते हैं

एफएएस के आकलन में महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत के पास वर्तमान में तैयार लॉन्चरों से जुड़े हथियारों की संख्या से अधिक परमाणु हथियार होने का अनुमान है। कुल 190 हथियारों में से लगभग 160 मौजूदा डिलीवरी सिस्टम से जुड़े बताए गए हैं, जबकि शेष भविष्य में उपयोग होने वाले डिलीवरी सिस्टम के लिए तैयार हो सकते हैं।

परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में लगातार मजबूती का संकेत

विशेषज्ञों के अनुसार, यह अंतर असामान्य नहीं है, क्योंकि कई परमाणु शक्तियां नए मिसाइल सिस्टम (जैसे भारत की अग्नि-प्राइम और के-4 मिसाइलें) के सेवा में आने से पहले ही उनके लिए हथियार तैयार रखना शुरू कर देती हैं ताकि परिचालन में देरी न हो।

परमाणु हथियारों के भंडार में संभावित बढ़ोतरी के बावजूद, भारत अपनी घोषित नो-फर्स्ट-यूज (एनएफयू) नीति पर दृढ़ता से कायम है। इस नीति के तहत भारत ने स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियारों का उपयोग पहले नहीं करेगा और केवल परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत ने 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद से कोई नया परमाणु परीक्षण नहीं किया है और स्वैच्छिक परीक्षण रोक बनाए रखी है, जो उसकी परमाणु नीति में निरंतरता को दशार्ता है। भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का विकास जमीन, समुद्र और हवा आधारित तीनों माध्यमों पर केंद्रित रहा है, जिसमें अतिरिक्त परमाणु हथियारों का उत्पादन भविष्य की जरूरतों और परिचालन तैयारियों का हिस्सा माना जा सकता है। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान और चीन की परमाणु क्षमताओं के बीच संतुलन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर रहती है।

संपादकीय

व्यापार घाटे का ब्रिक्स

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आगमन की भी पुष्टि हो चुकी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। कई समझौते परवान चढ़े। उनका विश्लेषण अलग से किया जाएगा। दरअसल हमने ईरान युद्ध के संदर्भ में इस शिखर सम्मेलन का विश्लेषण किया था। आज भारत की अर्थव्यवस्था, ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार और भारत के निरंतर घाटे की चर्चा कर रहे हैं। ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब भी ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। फिलहाल उनके बीच एक विनाशक, विध्वंसक युद्ध जारी है। ईरान ने उनके तेल ठिकानों, रिफाइनरियों, संयंत्रों पर ऐसे हमले किए हैं कि उनके उत्पादन खत्म हो गए हैं या वे भस्म हो गए हैं, नतीजतन दुनिया संकट में है। हालांकि अमरीका-इजरायल इस युद्ध के नरसंहारी चेहरे हैं। ईरान युद्ध के कारण अभी तक भारत को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय धक्का लग चुका है। यह अनुमान है, जबकि हकीकत इससे ज्यादा हो सकती है। इसी के कारण हमारा चालू खाता घाटा भी जीडीपी का 1.9 फीसदी से 2 फीसदी तक बढ़ चुका है। विशेषज्ञों के आकलन हैं कि 2026-27 की आखिरी विकास दर 6.5 फीसदी के करीब हो सकती है, लिहाजा एक तिमाही की 7.8 फीसदी विकास दर पर अधिक फुलफुलाना नहीं चाहिए। भारत ब्रिक्स देशों-चीन, रूस, अमीरात, सऊदी, ब्राजील-के साथ लगातार कारोबार करता रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि हम लगातार व्यापार-असंतुलन के शिकार हो रहे हैं और भारत आज तक निराश्रित, असहाय, लाचार है। आत्मनिर्भरता तो बहुत दूर की कौड़ी है। चीन के साथ भारत का व्यापार-घाटा 9.92 लाख करोड़ रुपए का है, तो रूस की तुलना में भारत 4.48 लाख करोड़ रुपए के घाटे में है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ करीब 2.34 लाख करोड़ रुपए और सऊदी अरब के साथ भी करीब 1.81 लाख करोड़ रुपए का व्यापार-घाटा हम झेल रहे हैं। ब्राजील सरीखे अपेक्षाकृत छोटे देश के साथ भी भारत का व्यापार-घाटा करीब 9579 करोड़ रुपए का है।

भारत ब्रिक्स देशों के साथ करीब 40 लाख करोड़ रुपए का कुल व्यापार करता है, जिसमें हमारा व्यापार-घाटा 21.14 लाख करोड़ रुपए का है। भारत का 2026 में अभी तक निर्यात 21.7 फीसदी है, जबकि आयात 41.5 फीसदी है। वैश्विक स्तर पर यह सूची बहुत लंबी है। बेशक ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, विदेश नीति, बहुपक्षीय व्यापार और अन्य सहयोगों का मंच है, लेकिन भारत सरीखे मुख्य किरदार वाले देश के आर्थिक-व्यापारिक अंतसंबंध असंतुलित हों, तो कब तक झेला जा सकता है? हमें पता है कि इस असंतुलन और घाटे की चर्चा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नहीं होगी, क्योंकि भारत सरकार स्वीकार ही नहीं करेगी कि वाकई व्यापारिक असंतुलन की स्थिति है। बहरहाल भारत पर आज करीब 225 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जाहिर है कि आय और व्यय, आयात और निर्यात में भारी असंतुलन होंगे, तो इतना कर्ज उठाना पड़ा है। ब्रिक्स के न्यू डवलपमेंट बैंक ने भी हमारी कई परियोजनाओं को पैसा दिया है। वह भी कर्ज ही होगा! दरअसल यह व्यापार-घाटा किसी एक सरकार के कार्यकाल का नहीं है। हमने दुर्लभ खनिज, फार्मा के कच्चे माल, यूरिया, मैन्युफैक्चरिंग के विभिन्न उपकरण आदि के उत्पादन पर गंभीर ध्यान ही नहीं दिया अथवा गंभीर प्रयास नहीं किए, लिहाजा दूसरे देशों, खासकर चीन, पर हमारा आश्रय बढ़ता रहा है। अलबत्ता मोबाइल निर्माण में हम विश्व के दूसरे स्थान के देश बन सकते हैं या करीब 2 लाख करोड़ रुपए के रक्षा-उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, तो अन्य वस्तुओं, सेवाओं, उपकरण, कच्चे माल के लिए भारत 21वीं सदी में भी मोहताज क्यों है? कच्चे तेल, एलपीजी, एलएनजी के आयात समझ में आते हैं, क्योंकि ऐसे स्रोत भारत में नगण्य हैं अथवा तलाशे जा रहे हैं, लेकिन टैक्निकल ग्रेड का 60 फीसदी यूरिया दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) और मिस्र से आज भी आयात क्यों करना पड़ रहा है? ईरान युद्ध के कारण फिलहाल यह बाधित है। हम पहले ईरान से भी कच्चा तेल आयात करते थे। रुपए में लेन-देन होता था। ईरान के करीब 60,000 करोड़ रुपए भारतीय बैंक में जमा होते थे। अब ब्रिक्स के मौके पर सवाल है कि क्या भारत ईरान से तेल खरीदने का अनुबंध एक बार फिर करेगा? इन आर्थिक सवालों पर प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संवाद के दौरान चर्चा जरूर करें। ज्यादा आयात के कारण जो घाटा हो रहा है, उससे निपटना होगा।

हादसे रोकने में नाकाम ट्रिपल इंजन सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली अनधिकृत अतिक्रमण और अवैध निर्माण से प्रभावित हो रही है। अदालत ने यह भी कहा था कि कई नागरिक एजेंसियां अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रही हैं। 14 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अनधिकृत निर्माण से जुड़े पुराने आदेशों और कार्रवाई की व्यवस्था की समीक्षा की। अदालत के समक्ष सीलिंग और अन्य वैधानिक कार्रवाई का मुद्दा भी आया। साफ था कि अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई का तंत्र मौजूद है, लेकिन चुनौती उसके प्रभावी क्रियान्वयन की है। मई 2026 में हाई कोर्ट ने एमसीडी इंजीनियरों पर सवाल उठाए थे। सत्य निकेतन हादसे से कुछ महीने पहले 23 मई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने जोन-ओ में अनधिकृत निर्माण पर बेहद गंभीर टिप्पणी की थी।

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक पुरानी 5 मंजिला पीजी इमारत ढहने से 7 छात्रों की मौत हो गई है। दिल्ली में 200 से ज्यादा ऐसे हॉस्टल और पीजी खतरनाक स्थिति में पाए गए हैं जिन पर अब प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में यह हादसा उस वक्त हुआ है जब ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं और एक खास इलाके में बने विश्व स्तरीय भारत मंडपम को इसकी मेजबानी के लिए सजाया-संवारा जा रहा है। बीते कुछ साल में कई अंतरराष्ट्रीय आयोजन कर चुकी इसी दिल्ली में दर्जनों लोग पहले तो पानी में डूबकर, फिर बिल्डिंग में लगी आग में जलकर और अब बिल्डिंग गिर जाने के चलते कुचलकर मर गए हैं। हर बार जांच, कार्रवाई और सुधार जैसे शब्द उछले, लेकिन ये सारे शब्द अगले हादसे के शोर में दब जाने का इंतजार भर करते रह गए। जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर की एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत के बाद भाजपा ने इसके लिए उस वक्त आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली महानगर निगम और दिल्ली सरकार को दोषी ठहराया था। दो साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, सत्ता बदल गई है, लेकिन लोग फिर से अप्राकृतिक मौत मरे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भाजपा गठबंधन, दिल्ली में भाजपा सरकार और दिल्ली महानगर निगम में भी भाजपा का बोर्ड है। इसके बावजूद हादसे दर हादसे हो रहे हैं। भाजपा ने लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनावों और दिल्ली नगर निगम के चुनावों में दावा किया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने से विकास भी तिगुनी गति से होगा।

विकास तो दूर रहा, दिल्ली हादसों से ही सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 3 जून 2026 को एक होटल-कम-रेस्तरां के निचले फ्लोर पर आग में कुल 22 लोगों की जान गई। अगस्त 2023 में ओखला में बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। सितंबर 2024 में करोल बाग में बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की मौत हुई, जनवरी 2025 में बिल्डिंग गिरने से 5 की मौत हुई, अप्रैल 2025 में मुस्तफाबाद में 3 बच्चों की मौत हुई, मई 2025 में पहाडगंज में दीवार गिरने से 3 की मौत हुई, अगस्त 2025 में घर की दीवार गिरने से जैतपुर इलाके के 6 लोग मर गए। इसी साल जुलाई 2026 में रोहिणी सेक्टर 16 में एक बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की और मई 2026 में साकेत में बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसी साल जून के महीने में फायर सेफ्टी विभाग ने बताया था कि उन्हें पिछले 5 महीने में ही बिल्डिंग गिरने से जुड़े 76 घटनाओं के बारे में फोन आए थे। 2025 में 544 और 2024 में कुल 464 हादसे हुए। इन हादसों में सिर्फ 2024 और 2025 में ही 46 लोगों की मौत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में इमारत गिरने की 349 घटनाएं हुईं। इनमें 43 लोगों की मौत और 315 लोग घायल हुए। वर्ष 2023 में 371 घटनाओं में 23 लोगों की जान गई और 171 लोग घायल हुए। दिल्ली में कुल कितनी अवैध इमारतें मौजूद हैं, इसका कोई सटीक या आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। दिल्ली के एक बड़े हिस्से में अनधिकृत कॉलोनियां और झुग्गी-झोंपड़ियां फैली हुई हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर बिना वैध नक्शे या नियमों के उल्लंघन के, निर्माण किए गए हैं। हालांकि, नगर निगम और सरकार के हालिया आंकड़े इसकी गंभीरता को दशार्ते हैं। केवल वर्ष 2025 में ही, दिल्ली निगम ने 4766 अनधिकृत इमारतों को बुक (चिन्हित) किया था। इसके अलावा समय-समय पर सैकड़ों निमार्णों को सील और ध्वस्त किया जाता रहा है।

सितंबर 2026 में दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक 5 मंजिला अवैध इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत के बाद सरकार ने 4 और 5 मंजिल से ऊंची सभी अवैध इमारतों को तुरंत सील करने का सख्त आदेश दिया है। मानसून से पहले एमसीडी द्वारा कराए गए सर्वे में करीब 32.55 लाख इमारतों की जांच की जानी थी, जिसमें से 29.94 लाख से अधिक इमारतों की जांच पूरी होने पर शुरूआती तौर पर केवल 27 इमारतों को असुरक्षित घोषित किया गया था, लेकिन इस सर्वे पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं क्योंकि अवैध रूप से बनी बहुमंजिला इमारतें इसमें पूरी तरह उजागर नहीं हो पातीं।

दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2006 में अदालत की निगरानी समिति बनाई गई थी। इसके बाद कई आदेशों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए गए। वर्ष 2017 में निगरानी समिति की शक्तियां बहाल करने और विशेष कार्यबल गठित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। इसके बावजूद दिल्ली में अवैध निर्माण की समस्या बनी रही। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2001 के आदेश का हवाला देते हुए 2020 के फैसले में दर्ज किया था कि दिल्ली में अनधिकृत निर्माण बढ़या गंभीर और खतरनाक प्रवृत्ति है। अदालत ने कहा था कि नियमों का पालन नहीं करने वालों में कानून का भय नहीं रह गया है और इसका प्रमुख कारण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होना है। दो दशक बाद भी यह टिप्पणी प्रासंगिक नजर आती है।

24 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली अनधिकृत अतिक्रमण और अवैध निर्माण से प्रभावित हो रही है। अदालत ने यह भी कहा था कि कई नागरिक एजेंसियां अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रही हैं। 14 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अनधिकृत निर्माण से जुड़े पुराने आदेशों और कार्रवाई की व्यवस्था की समीक्षा की। अदालत के समक्ष सीलिंग और अन्य वैधानिक कार्रवाई का मुद्दा भी आया। साफ था कि अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई का तंत्र मौजूद है, लेकिन चुनौती उसके प्रभावी क्रियान्वयन की है। मई 2026 में हाई कोर्ट ने एमसीडी इंजीनियरों पर सवाल उठाए थे। सत्य निकेतन हादसे से कुछ महीने पहले 23 मई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने जोन-ओ में अनधिकृत निर्माण पर बेहद गंभीर टिप्पणी की थी। सत्य निकेतन हादसे के बाद पुलिस कार्रवाई और मजिस्ट्रेट जांच के साथ एमसीडी ने भी अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हर हादसे के बाद सीलिंग और जांच शुरू करना ही पर्याप्त है। जब सुप्रीम कोर्ट वर्षों पहले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कह चुका है और दिल्ली हाई कोर्ट हाल तक एमसीडी इंजीनियरों की निगरानी में अनधिकृत निर्माण होने पर सवाल उठा रहा है, तो फिर निर्माण शुरू होने के समय ही उसे रोकने का तंत्र प्रभावी क्यों नहीं हो पाया। सत्य निकेतन हादसा इसी जवाबदेही की अगली परीक्षा है।

योगेंद्र योगी
स्वतंत्र लेखक

डोनाल्ड ट्रंप के गुरु हैं मोदी ?

क्या दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से चुनाव जीतने के नए-नए तरीके सीख रही है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत की चुनाव व्यवस्था का सार्वजनिक रूप से उल्लेख करते हुए, उसे अमेरिका के लिए उदाहरण के तौर पर पेश किया है। अगस्त में ट्रंप ने भारत के मतदाता पहचान पत्र और नागरिकता सत्यापन व्यवस्था का हवाला देते हुए अमेरिकी चुनावों में कड़े पहचान नियम लागू करने की वकालत की। सीधे यह कहना कि ट्रंप, नरेंद्र मोदी के शिष्य बन गए हैं, ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी को ट्रम्प फॉलो कर रहे हैं, दोनों नेताओं की राजनीति में कुछ दिलचस्प और विचित्र समानताएं जरूर दिखने को मिलती हैं। यही तुलना इस तरह के विचार को बल देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्षों में एक मजबूत राजनीतिक ब्रांड विश्व गुरु के रूप में भारत सहित सारी दुनिया में अपने आपको पेश किया है। समर्थक उन्हें विश्व मंच पर भारत की प्रभावी आवाज और विश्व गुरु के रूप में पिछले कई वर्षों से प्रस्तुत करते हैं। मोदी को विभिन्न देशों से अनेक सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। दुनिया के किसी भी राष्ट्रॉध्यक्ष को इतने कम समय में इतने सम्मान नहीं मिले हैं। किसी नेता की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता और उसकी चुनावी रणनीति तथा लंबे समय तक सत्ता में बने रहने को उसकी सफलता से जोड़कर देखा जाता है। ट्रंप की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार उनकी सीधी, आक्रामक और जोखिम लेने वाली शैली है। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने टैरिफ को आर्थिक और राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका में महंगाई और आर्थिक दबाव बना। आईएमएफ के अनुसार 2025 में अमेरिकी महंगाई पर टैरिफ का बड़ा असर दिखाई दिया। अमेरिका का सरकारी कर्ज 123.9 प्रतिशत जीडीपी की तुलना पर पहुंच गया। कुछ ऐसी ही स्थिति भारत की है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत के ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। अब असली समानता अर्थव्यवस्था से ज्यादा चुनावी राजनीति में दिखाई देने लगी है। भारत की चुनावी राजनीति में मतदाता पहचान, नागरिकता, मतदाता सूची और सत्यापन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। भारत में चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पिछले वर्षों में चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारे मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं मुद्दों को अमेरिकी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भारत की चुनाव व्यवस्था का उदाहरण देते हुए सेव एक्ट के समर्थन में नागरिकता प्रमाण और फोटो आईडी जैसी शर्तों की वकालत अमेरिका में शुरू कर दी है। भारत की एसआईआर और अमेरिका में प्रस्तावित चुनावी नियमों को समान बताना सही नहीं होगा। दोनों देशों की चुनाव व्यवस्था, संघीय ढांचा और मतदाता पंजीकरण प्रणाली अलग है। इसके बाद भी ट्रंप भारत की व्यवस्था को अमेरिका में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं, सबसे दिलचस्प मुद्दे रेवड़ी या चुनाव के पहले मतदाताओं को आर्थिक सहायता देकर अपने पक्ष में करना। 9 सितंबर 2026 को ट्रंप ने घोषणा की है, यदि रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत बनाए रखती है। तो अमेरिकी वयस्क नागरिकों को 5,000 डॉलर का डिविडेंड दिया जाएगा। इसका संभावित खर्च एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक होगा। भारत में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कथित तौर पर 15 लाख रुपये चुनाव जीतने पर देने का वादा किया गया था, जिसे बाद में चुनावी जुमला करार दिया गया। चुनाव के पहले भारत में इस तरह की घोषणा पिछले कई चुनाव में देखने को मिल रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में इसे फ्री की रेवड़ी कहते थे। चुनाव के ठीक पहले अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही रास्ता अखत्यार किया है।

यहीं से वर्तमान राजनीति के नए समीकरण शुरू होते हैं। बड़ी संख्या में मतदाताओं को नगद राशि देकर अपने पक्ष में मतदान कराकर चुनाव जीतना। पहले नेता की छवि, राजनीतिक दल की विचारधारा, राष्ट्रवाद, आम जनता के लिए घोषणा पत्र, जिसमें सरकार किस तरह से काम करेगी इसका उल्लेख होता था। विपक्षी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर उनकी स्थिति को कमजोर करना चुनाव लड़ने का माध्यम होता था। पिछले एक दशक में सारी दुनिया के देशों में राजनीति की दिशा और दशा बदली है। जो सत्ता में काबिज है वह सत्ता छोड़ना नहीं चाहता है। चीन, अमेरिका, इजराइल एवं अन्य लोकतांत्रिक देशों के शासक अपना पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था वह तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। क्या यह मोदी मॉडल है? कहना जल्दबाजी होगी। इतना जरूर कहा जा सकता है, जिस तरह भारतीय राजनीति में नेतृत्व की व्यक्तिगत छवि, अधिकारों का केंद्रीकरण, जनसंपर्क, राष्ट्रहित, धार्मिक ध्रुवीकरण, फ्री की रेवड़ी जैसी योजनाएं चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं, वैसी ही प्रवृत्तियां अमेरिकी राजनीति में भी दिखाई दे रही हैं। असली सवाल यह नहीं है, मोदी ट्रंप के गुरु हैं या नहीं। असली सवाल यह है, क्या दुनिया की लोकतांत्रिक राजनीति अब एक-दूसरे देश से चुनाव जीतने की तकनीक सीख रही है? ट्रंप भारत से सबक ले रहे हैं, तो यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकतांत्रिक शक्ति की उपलब्धि मानना होगा। लोकतंत्र की सफलता केवल चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि निष्पक्ष मतदाता सूची, स्वतंत्र संस्थाओं, पारदर्शी चुनाव, मजबूत अर्थव्यवस्था और नागरिक अधिकारों की रक्षा से होती है। इस दृष्टि से भविष्य में सवाल पूछेगा, पहले भारत व्यवस्था में अमेरिका से प्रेरणा लेता था, अब समय बदला है। अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र भारत से चुनावी राजनीति सीख रहा है? अगर ऐसा है, तो इसे भारत की बड़ी वैश्विक उपलब्धि माना जाएगा। जिस तरह की शासन व्यवस्था विकसित हो रही है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक अधिकार धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

लेखक-सनत जैन

बिहार में बाढ़ की बड़ी चुनौती के बीच राहत का सहारा

बिहार इस समय बाढ़ की गंभीर चुनौती से गुजर रहा है। राज्य की प्रमुख नदियों गंगा, कोसी और गंडक के जलस्तर ने कई जिलों में जनजीवन को प्रभावित किया है। 14 जिलों के 82 से अधिक प्रखंडों और सैकड़ों ग्राम पंचायतों में लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। कहीं घरों में पानी घुस गया है तो कहीं गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। खेतों में पानी भरने से खेती प्रभावित हुई है और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसे समय में सबसे बड़ी चुनौती बाढ़ के पानी के बीच प्रभावित परिवारों तक भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और सुरक्षित आवागमन की सुविधा पहुंचाना है। बाढ़ की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के करीब 40 लाख से अधिक लोग इसके प्रभाव में बताए जा रहे हैं। पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जैसे जिलों में बाढ़ का असर व्यापक है। कई स्थानों पर पानी गांवों के भीतर तक पहुंच गया है। निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए सुरक्षित स्थान तक पहुंचना आसान नहीं है। सड़कों और संपर्क मार्गों पर पानी आने के कारण नाव ही कई जगहों पर आवागमन का प्रमुख साधन बनी हुई है।

हालांकि बाढ़ की स्थिति एक जैसी नहीं है। कोसी और सोन के जलस्तर में कमी आने से कुछ इलाकों में राहत की उम्मीद बनी है। गंडक के जलस्राव में भी स्थिरता दिखाई दे रही है। लेकिन गंगा का जलस्तर अब भी चिंता का कारण बना हुआ है। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर 36.80 मीटर दर्ज किया गया, जो वर्ष 2021 में दर्ज किए गए पिछले उच्चतम बाढ़ स्तर से थोड़ा ऊपर है। ऐसे में नदी किनारे बसे गांवों और निचले क्षेत्रों में प्रशासन को लगातार निगरानी रखनी पड़ रही है। बाढ़ का पानी घटने की स्थिति में भी खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से आने वाले पानी के कारण जलस्तर में दोबारा वृद्धि हो सकती है।

बाढ़ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सवाल प्रभावित लोगों के भोजन का होता है। जिन परिवारों के घर पानी से घिर जाते हैं, उनके लिए घर में रखा अनाज और खाना पकाने की व्यवस्था लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में सैकड़ों सामुदायिक रसोइयां संचालित की जा रही हैं। इन रसोइयों के माध्यम से लाखों लोगों को सुबह और शाम भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह व्यवस्था केवल भोजन पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बाढ़ में फंसे परिवारों के लिए जीवन की सबसे जरूरी जरूरत पूरी करने का माध्यम बनी हुई है। राहत शिविरों में बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था और महिलाओं के लिए आवश्यक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराने की पहल भी महत्वपूर्ण है।

बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ उनके अस्थायी रहने की व्यवस्था भी प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। राहत शिविरों में हजारों लोगों के रहने, भोजन और उपचार की व्यवस्था की गई है। जिन परिवारों के मकान पानी से घिर गए हैं या जिनके घरों में रहना सुरक्षित नहीं है, उनके लिए ऐसे शिविर अस्थायी आश्रय का काम कर रहे हैं। इन शिविरों में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक बाढ़ का पानी रहने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

बाढ़ के बाद सबसे अधिक चिंता बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को लेकर होती है। सामान्य परिस्थितियों में अस्पताल तक पहुंचना आसान होता है, लेकिन पानी से घिरे गांवों में यह काम कठिन हो जाता है। इसी वजह से प्रभावित इलाकों में चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं और नावों के माध्यम से भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। नाव से चलने वाली चिकित्सकीय व्यवस्था उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहां सड़क संपर्क बाधित हो चुका है। दवाइयों की उपलब्धता के साथ चिकित्सकीय दलों की नियमित मौजूदगी बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत दे सकती है।

प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को तिरपाल और सूखा राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। एक लाख से अधिक तिरपाल और हजारों सूखा राशन पैकेट वितरित किए जाने की जानकारी है। जिन परिवारों के घरों में पानी घुस गया है, उनके लिए तिरपाल तत्काल आश्रय उपलब्ध कराने में मददगार हैं। वहीं सूखा राशन उन क्षेत्रों में जरूरी है जहां सामान्य भोजन सामग्री पहुंचाना कठिन हो रहा है। बाढ़ केवल मनुष्य ही नहीं, पशुधन को भी प्रभावित करती है। ग्रामीण परिवारों के लिए पशु उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। इसलिए हजारों क्विंटल पशुचारा वितरित किया जाना राहत कार्य का जरूरी हिस्सा है।

आवागमन की समस्या से निपटने के लिए बड़ी संख्या में नावों का संचालन किया जा रहा है। बाढ़ के समय नाव केवल यातायात का साधन नहीं रहती, बल्कि भोजन, दवा और राहत सामग्री पहुंचाने से लेकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक निकालने का महत्वपूर्ण माध्यम बन जाती है। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें भी तैनात की गई हैं। इन दलों की मौजूदगी किसी आकस्मिक स्थिति में तेजी से बचाव अभियान चलाने के लिए जरूरी है। खासकर रात के समय या अचानक जलस्तर बढ़ने की स्थिति में प्रशिक्षित बचाव दलों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

बाढ़ के दौरान अंतिम संस्कार जैसी मानवीय और सामाजिक जरूरतें भी प्रभावित होती हैं। नदी किनारे बने अनेक श्मशान घाट पानी में डूब जाने से परिवारों के सामने कठिन परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने तथा आवश्यक सहयोग देने की व्यवस्था करनी चाहिए। संकट की घड़ी में सम्मानजनक अंतिम संस्कार की सुविधा भी राहत कार्य का अभिन्न हिस्सा है।

बिहार में इस वर्ष बारिश का कुल आंकड़ा सामान्य से कम रहा है, लेकिन सितंबर में वर्षा सामान्य से अधिक दर्ज की गई है। यही असमान वर्षा बाढ़ की स्थिति को जटिल बना रही है। आने वाले दिनों में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, इसलिए नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासन के लिए भी चुनौती यही है कि राहत व्यवस्था केवल वर्तमान स्थिति तक सीमित न रहे, बल्कि अगले कुछ दिनों की संभावित बारिश और जलस्तर को ध्यान में रखकर पहले से तैयारी रखी जाए।

बाढ़ के बीच सबसे बड़ी उम्मीद राहत और बचाव व्यवस्था की मजबूती से जुड़ी है। सामुदायिक रसोइयों से भोजन, राहत शिविरों में आश्रय, नावों से आवागमन, चिकित्सा शिविरों से उपचार, बच्चों के लिए दूध, महिलाओं के लिए जरूरी सामग्री और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था यह बताती है कि संकट के समय राहत तंत्र को कई स्तरों पर काम करना पड़ता है। लेकिन राहत की सफलता का वास्तविक पैमाना यह होगा कि सबसे दूर और सबसे अधिक प्रभावित गांव तक सहायता कितनी जल्दी पहुंचती है। बिहार के सामने अभी पानी घटने का इंतजार ही नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित रखने और बाढ़ के बाद उनके जीवन को फिर से सामान्य बनाने की चुनौती भी है। यही समय है जब प्रशासन, बचाव दल और स्थानीय समुदाय मिलकर संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम करें, ताकि बाढ़ से घिरे लाखों लोगों को राहत केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर महसूस हो सके।

(लेखक - कांतिलाल मांडोत)
(वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार स्तम्भकार)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

आलेख

चिंताजनक हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध की कोशिशें

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले बीकेसी पुलिस और मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया. इनके पास से पीएमओ का फर्जी परिचय पत्र और हथियार मिलना मामले की गंभीरता को बढ़ाता है वही ऐसे समय में जब देश की राजधानी नईदिल्ली में 11 से 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं सुरक्षा में कोई चूक क्षम्य नहीं है।

आपको बता दें कि मुंबई की इस घटना के मुख्य आरोपी रोहन पारेख और उसके बॉडीगार्ड दिलीप कुंडे को मंगलवार को अदालत में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 11 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. सुरक्षा एजेंसी मान रहीं हैं कि मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली से ठीक पहले तीन संदिग्धों की गिरफ्तारी और उनके पास से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का फर्जी पहचान पत्र, हथियार तथा जिंदा कारतूस बरामद होना एक अत्यंत संवेदनशील और चिंताजनक घटना है। यह केवल एक आपराधिक साजिश का पदार्फाश नहीं है, बल्कि देश की सर्वोच्च सुरक्षा प्रणाली में मौजूद उन संभावित खामियों की ओर भी इशारा करता है, जिनका फायदा उठाकर असामाजिक और राष्ट्रविरोधी तत्व इतनी गहराई तक घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी शीर्ष जननेता, विशेषकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा केवल एक व्यक्ति का विषय नहीं होती, बल्कि यह राष्ट्रीय संप्रभुता, साख और आंतरिक स्थिरता से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में इस गंभीर चूक और साजिश की तह तक जाना बेहद जरूरी है। मुंबई पुलिस की स्थानीय खुफिया इकाई और आतंकवाद विरोधी दस्ते की सतर्कता की निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए, जिनकी समय रहते कार्रवाई से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, इस घटना के जो पहलू सामने आ रहे हैं, वे कई असहज करने वाले सवाल खड़े करते हैं। संदिग्धों के पास से पीएमओ का फर्जी पहचान पत्र मिलना इस बात का प्रमाण है कि साजिशकर्ताओं ने बेहद शातिराना योजना बनाई थी। सवाल यह उठता है कि क्या इन संदिग्धों का इरादा रैली स्थल के उस उच्च-सुरक्षा क्षेत्र तक पहुंचना था, जहां केवल अधिकृत अधिकारियों, विशिष्ट अतिथियों और सुरक्षाकर्मियों को ही जाने की अनुमति होती है? यदि वे फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर सुरक्षा घेरे को भेदने में सफल हो जाते, तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती थी, इसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

मौजूदा मामले में बचाव पक्ष के वकीलों ने रोहन का पक्ष रखते हुए पुलिस के दावों को खारिज करने की कोशिश की. रोहन के वकील ने कोर्ट के सामने दावा किया कि रोहन पारेख कोई अपराधी नहीं बल्कि खुद धोखाधड़ी का शिकार हुआ है. वकील के मुताबिक, रोहन को तरुण नाम के एक शख्स के जरिए पीएमओ के अतिरिक्त सचिव के नाम से एक ईमेल प्राप्त हुआ था. इसी ईमेल के आधार पर उसे पीएमओ से जुड़ी जानकारी दी गई थीअदालत में सुनवाई के दौरान जज ने बचाव पक्ष के वकील से सीधा सवाल पूछा कि क्या आरोपी को प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यक्रम के सुरक्षा प्रोटोकॉल की कोई जानकारी थी?

इस सवाल पर वकील ने दलील दी कि रोहन की नीयत खराब नहीं थी. घटना से एक दिन पहले वह सिर्फ व्यवस्था देखने कार्यक्रम स्थल के आसपास गया था और उसने वहां पास के ही एक मॉल से परफ्यूम भी खरीदा था. लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपी ने एक रात पहले आयोजन स्थल के आसपास रेकी भी की थी.मामले में गिरफ्तार दूसरा आरोपी 45 साल का दिलीप कुंडे है. पुलिस ने इसे कल्याण से दबोचा है. वह साल 2024 से रोहन पारेख के बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहा है. जांच में सामने आया है कि दिलीप पूर्व सीआईएसएफ जवान है और जिस रिवॉल्वर के साथ वह पकड़ा गया है, उसका लाइसेंस उत्तर प्रदेश का है.

इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों को पता चला है कि दिलीप कुंडे का परिवार मुख्य रूप से ड्रोन से जुड़े कारोबार में शामिल है.

खार इलाके का रहने वाला मुख्य आरोपी रोहन पारेख एक बेहद रसूखदार और बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता है. उसके पिता का नाम प्रेमाल पारेख बताया जा रहा है. सुनवाई के दौरान रोहन का पूरा परिवार कोर्ट रूम में मौजूद था.

फिलहाल, पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आखिर रोहन ने पीएमओ का फर्जी पहचान पत्र किस मकसद से बनवाया था. क्या उसे सच में किसी तरुण नाम के शख्स ने झांसा दिया था या फिर यह सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोई सोची-समझी साजिश थी? पुलिस अब फरार चल रहे तीसरे आरोपी प्रथमेश बागूर की तलाश में छापेमारी कर रही है.

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा देश की सबसे विशिष्ट एजेंसी, विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के पास होता है। इसके अलावा, राज्य की स्थानीय पुलिस, राज्य खुफिया विभाग और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां मिलकर बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार करती हैं। किसी भी रैली या बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले पूरे इलाके की सघन नाकाबंदी होती है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन प्रोटोकॉल के तहत हर बारीक बिंदु की समीक्षा की जाती है। इस प्रकार की फूलप्रूफ व्यवस्था के बावजूद संदिग्धों का फर्जी आईडी और अवैध हथियारों के साथ रैली स्थल के आसपास के क्षेत्र तक पहुंच जाना यह दशार्ता है कि स्थानीय स्तर पर कहीं न कहीं खुफिया तंत्र में कोई अंधा मोड़ रह गया था। यह घटना हमें अतीत की उन दुखद राष्ट्रीय त्रासदियों की याद दिलाती है, जहां सुरक्षा तंत्र में जरा सी ढील या खुफिया सूचनाओं की अनदेखी के कारण देश ने अपने महान नेताओं को खोया है। इतिहास से सीख लेना ही परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है। आधुनिक समय में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी हो चुकी हैं। आज केवल पारंपरिक खतरों या सीधे हमलों से ही नहीं, बल्कि अंदरूनी घुसपैठ, फर्जी डिजिटल या भौतिक पहचान-पत्रों के जरिए छद्म नाम से किए जाने वाले हमलों से भी निपटना पड़ रहा है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह, अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क और संदिग्ध आपराधिक तत्वों के बीच बनता यह नया गठबंधन आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा नासूर बनता जा रहा है।

एक रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसियों को अब इस मामले को केवल एक स्थानीय आपराधिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे छिपे पूरे नेटवर्क का पदार्फाश होना आवश्यक है। सबसे पहला सवाल यह है कि यह फर्जी पीएमओ आईडी कहां और किसके द्वारा बनाई गई? क्या इसके पीछे किसी अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय साजिशकर्ता गिरोह का हाथ है? इन संदिग्धों को हथियार कहां से सप्लाई किए गए और इनका वास्तविक वित्तीय तथा रणनीतिक मददगार कौन है? जब तक इस साजिश की पूरी कड़ियों को नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक ऐसे खतरों को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, इस घटना से सीख लेते हुए प्रशासनिक और सुरक्षा स्तर पर व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। प्रथम, उच्च-सुरक्षा आयोजनों के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रवेश पासों और पहचान-पत्रों में क्यूआर कोड, बायोमेट्रिक सत्यापन और होलोग्राम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का अनिवार्य समावेश होना चाहिए, ताकि मौके पर ही उनकी प्रमाणिकता जांची जा सके। द्वितीय, स्थानीय स्तर पर अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तृतीय, राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में सूचनाओं के आदान-प्रदान और समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करना होगा। राजनीतिक रैलियां लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं, जहां नेता जनता से सीधे संवाद करते हैं। लेकिन वीआईपी सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। मुंबई में पकड़े गए संदिग्धों की यह घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। गनीमत रही कि समय रहते खतरा टल गया, लेकिन हर बार किस्मत सुरक्षा घेरे की खामियों को नहीं ढक सकती। पीएमओ का फर्जी कार्ड बनाने से लेकर तमाम घटनाचक्र गंभीरता से जांच का विषय है देश के दुश्मन ऐसे किसी भी षड्यंत्र की आड़ में अप्रिय वारदात को अंजाम दे सकते हैं इस से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं) (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

दिल्ली के करावल नगर में युवक की पीट-पीटकर हत्या

नई दिल्ली, 12 सितंबर (वेब वार्ता)। पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है।

मृतक की पहचान अंकुर एन्क्लेव निवासी राजकुमार (44) के रूप में हुई है। वह पेंटर का काम करते थे। स्वजन के अनुसार, बृहस्पतिवार रात करीब तीन-चार लोगों ने राजकुमार की पिटाई की। गंभीर हालत में उन्हें पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बल्ले-बल्ले, परिवार को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज

नई दिल्ली, 12 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों (कंस्ट्रक्शन वर्कर्स) और उनके आश्रित परिवारों को अब कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उपराज्यपाल सरदार टीएस संधू ने दिल्ली बिल्डिंग वर्कर्स हेल्थ स्कीम को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 2.7 लाख से अधिक पंजीकृत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को सालाना दो लाख रुपये तक का इलाज उपलब्ध होगा। वहीं, परिवार के लिए सालाना 10 लाख रुपये की समग्र सीमा तय की गई है। इससे पंजीकृत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उनके आश्रित परिवारों को इलाज के खर्च से जुड़ी आर्थिक चिंता से राहत देने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।

ब्रिक्स सम्मेलन के चलते दिल्ली में ट्रैफिक पर पाबंदियां, कई रास्तों पर डायवर्जन

नई दिल्ली, 12 सितंबर (वेब वार्ता)। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के चलते दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। भारत मंडपम और प्रगति मैदान के आसपास के क्षेत्रों के साथ-साथ मध्य दिल्ली को दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर भी जरूरत के अनुसार डायवर्जन और यातायात प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।

दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार, ये यातायात व्यवस्थाएं सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक प्रभावी रहेंगी। वीआईपी मूवमेंट के दौरान कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी या डायवर्ट की जा सकती है। रिंग रोड, मथुरा रोड, भैरों मार्ग, तिलक मार्ग, इंडिया गेट और सी-हेक्सागन के आसपास यातायात को आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा सरदार पटेल मार्ग, पटेल रोड, एनएच-48 और परेड रोड पर भी अलग-अलग स्थानों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।

संजय राउत बोले- चीन से रिश्ते सुधारने से पहले अपनी जमीन वापस मांगें

नई दिल्ली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत पहुंचने के बीच शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सवाल किया है। राउत ने कहा कि यदि भारत और चीन के रिश्तों में सुधार की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री मोदी को चीन से लद्दाख और गलवान से पीछे हटने तथा भारत की जमीन वापस करने की बात भी करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि चीन के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि चीन के राष्ट्रपति के भारत आने पर प्रधानमंत्री को यह भी पूछना चाहिए कि लद्दाख और गलवान में चीन जहां आया है।

जामिया छात्रावास प्रदर्शन

आइसा ने छात्रों की पिटाई का आरोप लगाया, विवि का इनकार

नई दिल्ली, 12 सितंबर (वेब वार्ता

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जम्मू-कश्मीर छात्रावास की छात्राओं के विरोध-प्रदर्शन के बीच, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने शनिवार को सहायक प्रॉक्टर पर छात्राओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया, हालांकि विश्वविद्यालय ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने दावा किया कि शुक्रवार देर रात कुछ छात्रों ने छात्रावास के दो गेट तोड़ दिए और प्रॉक्टर की टीम के सदस्यों के साथ मार-पीट की। जामिया में शनिवार को विरोध-प्रदर्शन का तीसरा दिन है। यह प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब कुछ छात्राओं ने मेस में परोसे जा रहे खराब गुणवत्ता के खाने की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि खाने में कीड़े मिले थे।

छात्राएं छात्रावास मेस के मौजूदा ठेकेदार का ठेका रद्द करने, मेस में महिला कर्मी की नियुक्ति करने और छात्रावास पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। वह आश्वासन चाहती हैं कि विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आइसा ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय छात्रों की मांगों के संबंध में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने में विफल रही है। आइसा ने यह भी आरोप लगाया कि सहायक प्रॉक्टर मकसूद अहमद मलिक ने शुक्रवार तड़के करीब एक बजे छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीएसडब्ल्यू) कार्यालय के पास छात्राओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की।

आरोप लगाया

छात्र संगठन का आरोप है कि एक छात्रा का मोबाइल फोन तब छीन लिया गया, जब वह घटना की रिकॉर्डिंग कर रही थी। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि विरोध के पहले ही दिन में छात्राओं की अधिकतर मांगे मान ली गई थीं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर स्थिति को और गंभीर बनाने का आरोप लगाया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक प्रवक्ता ने कहा, छात्राओं ने छात्रावास के दो गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे सभी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, और प्रॉक्टर टीम के सदस्यों के साथ बदसलूकी की।

दिल्ली-एनसीआर में अगले तीन दिन तक बारिश के आसार

नई दिल्ली, 12 सितंबर (वेब वार्ता)। मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार, मौसम में आए बदलाव के कारण शनिवार से लेकर अगले तीन दिनों तक दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी।

दूसरी ओर, बारिश और तेज हवाओं के कारण दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है, और हवा अब ह्यग्रीन जोनह्ण में पहुंच चुकी है। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, 12 सितंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) 85 से 55 प्रतिशत के बीच रहेगी। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।

13 सितंबर को तापमान थोड़ा बढ़कर 32 डिग्री अधिकतम और 26 डिग्री न्यूनतम तक पहुंच सकता है, लेकिन आर्द्रता 90 प्रतिशत तक रहेगी। इस दिन भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। 14 सितंबर को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। 15 सितंबर को पारा और गिरकर 24 डिग्री तक जा सकता है, और हल्की बारिश भी हो सकती है। 16 सितंबर को भी तापमान 31 और 25 डिग्री के बीच रहेगा, और हल्की बारिश होगी। हालांकि, 17 सितंबर को मौसम में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

प्रधानमंत्री आवास का भी निरीक्षण कराए भाजपा: आप

नई दिल्ली, 12 सितंबर (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर छह का निरीक्षण करेगी जहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे और उसने मांग की कि प्रधानमंत्री आवास का भी इसी तरह निरीक्षण कराया जाना चाहिए।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस बंगले की कथित भव्यता को लेकर लगातार झूठ बोलती रही है। उन्होंने दावा किया कि निरीक्षण के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। आतिशी ने एक वीडियो संदेश में कहा, भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री के फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आवास के बारे में लगातार झूठ फैलाया। उसने कहा कि वहां स्विमिंग पूल है, सोने का कमोड है, मदिरालय है और भी ऐसी कई अन्य बातें कहीं। मुझे खुशी है कि दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति ने इस आवास का निरीक्षण करने का फैसला किया है। सब कुछ 14 सितंबर को साफ हो जाएगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास का भी निरीक्षण कराए जाने की मांग करते हुए कहा, पूरा देश करोड़ों रुपये में बने प्रधानमंत्री आवास को भी देखेगा। आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जब मुख्यमंत्री के पद पर थे, उस समय वह सिविल लाइंस के फ्लैगस्टाफ रोड स्थित इस बंगले में रहते थे। भाजपा ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इस बंगले के मरम्मत कार्य को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और इसे ह्यशीशमहलह्ण बताते हुए इस पर अत्यधिक खर्च किए जाने का आरोप लगाया था। केजरीवाल के इस्तीफा देने और आवास खाली करने के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इसके अंदरूनी हिस्सों का विस्तृत ऑडिट किया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार इस संपत्ति को अतिथि गृह में बदलने और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी निजी आतिथ्य कंपनियों को सौंपने की योजना बना रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार रजत शर्मा के व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा की

नई दिल्ली, 12 सितंबर (वेब वार्ता)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई फेसबुक और यूट्यूब खातों को पत्रकार रजत शर्मा के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोका है और इन मंचों को ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बने डीपफेक वीडियो भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 24 अगस्त को इंडिया टीवी के चेयरमैन और प्रधान संपादक के पक्ष में और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ फैसला दिया। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि शर्मा ह्यमेटा प्लेटफॉर्म्स इंकह्ण और ह्यगूगल एलएलसीह्ण (जो क्रमश: फेसबुक और यूट्यूब का संचालन करते हैं) से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे ऐसी किसी भी सामग्री के खिलाफ संपर्क कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके नाम, शक्ल-सूरत, छवि, आवाज, फोटो, वीडियो या उनके व्यक्तित्व के किसी अन्य पहलू का दुरुपयोग, अनुचित इस्तेमाल या शोषण करती हो। अदालत ने आदेश दिया, संबंधित प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर अनुरोध स्वीकार करेंगे और उसके बाद 36 घंटे के भीतर कार्रवाई करेंगे।

शर्मा के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल एक जाना-माना पत्रकार है जिसकी छवि बेदाग है और वह दो दशकों से अधिक समय से भारतीय टेलीविजन का चेहरा हैं। वकील ने अपनी दलील में कहा कि फेसबुक पर कई खातें गलत जानकारी प्रसारित कर रहे हैं। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकी का गलत इस्तेमाल करके ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं जिनमें वादी की बदली हुई या हेर-फेर की गई तस्वीरें, आवाज और व्यक्तित्व की अन्य विशेषताएं दिखाई या सुनाई दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ यूट्यूब चैनल भी डीपफेक वीडियो प्रसारित कर रहे है। अदालत ने संज्ञान में लिया कि प्रतिवादियों को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने तय समय के भीतर मुकदमे का कोई जवाब दाखिल नहीं किया, और शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने इससे पहले शर्मा के व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था और आपत्तिजनक सामग्री तक पहुंच बाधित करने तथा उसे हटाने का निर्देश दिया था।

दिल्ली के नंद नगरी में 5 मामलों में वांछित बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली, 12 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस ने नंद नगरी इलाके से एक सक्रिय अपराधी को गिरफ्तार किया है। वह हत्या की कोशिश, लूटपाट और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन जैसे पांच पुराने आपराधिक मामलों में शामिल था। पुलिस ने अपराधी के पास से दो अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए।

दिल्ली पुलिस ने लूट के मामले में फरार आदतन अपराधी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 12 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस ने नबी करीम थाना क्षेत्र में लूट के मामले में एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने शनिवार को जानकारी दी कि आरोपी चार पुराने आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और वह लगातार जांच से बच रहा था।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि नबी करीम इलाके में एक व्यक्ति का मोबाइल फोन लूटा गया था। इस संबंध में 27 अगस्त को बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की

गई थी। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता बिहार का रहने वाला है, जो दिल्ली आया था और पहाड़गंज के एक होटल में ठहरा हुआ था। जब वह पहाड़गंज पुल से होते हुए पहाड़गंज इलाके की ओर जा रहा था, तो तीन लड़कों ने उसे रोका और ब्लेड दिखाकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। जांच के दौरान दो आरोपियों अजीम और यश उर्फ यासी को गिरफ्तार किया गया। अजीम को 30 अगस्त और यश उर्फ यासी को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने इस मामले में मुख्य आरोपी मोहित की संलिप्तता का खुलासा किया।

दिल्ली के नंद नगरी इलाके में तीन घरों पर हमला, अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग और पत्थरबाजी

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में फायरिंग से सनसनी फैल गई। कुछ अज्ञात लोगों ने शुक्रवार रात कथित तौर पर तीन घरों के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की और पास में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच कर रही है।

गोलीबारी की यह घटना नंद नगरी थाना इलाके के डी-2 ब्लॉक में हुई। अज्ञात बदमाशों ने तीन घरों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें परिवारों के लोग बाल-बाल बचे। वहीं, एक वीडियो में अज्ञात हमलावर गोली

चलाते हुए और पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दिए। एक महिला ने बताया कि हमारे घरों पर करीब 50 अज्ञात लोगों ने हमला किया। सभी लोगों ने मास्क लगा रखे थे।

महिला ने आरोप लगाया कि 7 साल पहले उनकी बेटी को लेकर एक विवाद हुआ था। इसके बाद से अक्सर घर के बाहर फायरिंग की जाती है और कभी पथराव किया जाता है। हमारे लड़कों को मारा पीटा जाता है। उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है। हमारे बच्चों को गोली मारने की भी धमकी दी जाती है। पीड़िता ने कहा कि देर रात भी हमारे तीन घरों पर हमले हुए हैं। यहां फायरिंग और पथराव किया गया है। परिवार के सभी लोग ऊपर थे। अगर हम लोग ऊपर नहीं होते तो परिवार के किसी सदस्य की जान जा सकती थी। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को लगातार खतरा है। इससे पहले, शुक्रवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में एक युवक ने पड़ोस में एक महिला पर फायरिंग के बाद खुद को गोली मार ली। इसमें युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई।

सबूत इकट्ठा किये गये

शुरुआती जांच में पता चला कि नीरज ने पहले पड़ोस में रहने वाली राजवती पर गोली चलाई और फिर रिवॉल्वर से खुद के सिर में गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना में घर की पहली मंजिल पर एक कमरे में लीला राम के बेटे नीरज (32 वर्ष) को खून से लथपथ हालत में पाया गया था और पास ही एक रिवॉल्वर पड़ी मिली। शुरुआती जांच में पता चला कि रिवॉल्वर का लाइसेंस मृतक नीरज के पिता के नाम पर था। वहीं, घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और घटना वाली जगह से जरूरी सबूत इकट्ठा किए गए।

दिल्ली पुलिस ने सिंघु बॉर्डर पर खालिस्तान-समर्थक ग्रैफि टी के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ़्तार

नई दिल्ली, 12 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर सिंधु बॉर्डर पर खालिस्तान समर्थक भित्तिचित्र बनाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दिल्ली और हरियाणा राज्यों के बीच स्थित सिंधु सीमा पर दीवारों पर आपत्तिजनक नारे और भित्तिचित्र 6 सितंबर को बनाए गए थे। प्रतिबंधित समूह सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक्स पर एक पोस्ट में इस कृत्य की जिम्मेदारी ली थी।

जांचकताओं को सिंधु सीमा पर लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों के बारे में सुराग मिले, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों में से एक पन्नू के सीधे संपर्क में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब विदेशों में सक्रिय खालिस्तान समर्थक संगठनों ने पाकिस्तान की अंतर-सेवा खुफिया (आईएसआई) के सीधे निर्देशों के तहत अपने परिचालन ढांचे में बदलाव किया और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई से बचने के लिए हिंसक अपराध से ध्यान हटाकर राजनीतिक प्रचार की ओर रुख किया। अब जब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां खालिस्तान मुद्दे पर भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो इन समूहों ने अपने काम करने के तरीके को बदलने का फैसला किया है। विदेशों में खालिस्तान आंदोलन हिंसक आंदोलन की बजाय तेजी से एक राजनीतिक अभियान की ओर बढ़ रहा है।

इस आंदोलन को नियंत्रित करने वाली पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ने खालिस्तान समर्थक समूहों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वे खुले तौर पर गैंगस्टरों के साथ संपर्क न करें जैसा कि वे इन दिनों करते आ रहे हैं। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि यह बदलाव भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय के मद्देनजर हुआ है।

अधिकारी ने कहा, यह कार्रवाई इसलिए संभव हो पाई क्योंकि ये खालिस्तानी समूह हिंसा, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में लिप्त थे। विदेशों में आपराधिक गिरोहों के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों ने एजेंसियों को हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जघन्य अपराधों के लिए उन पर कड़ी कार्रवाई करने का अवसर दिया। आईएसआई खालिस्तान समर्थक समूहों, जैसे कि एसएफजे, को प्रासंगिक बनाए रखने के महत्व को समझती है। उन्हें इस मुद्दे को विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिसके तहत जनमत संग्रह आयोजित करना, मार्च निकालना और पंजाब से अलग खालिस्तान की मांग करना शामिल है।

दिल्ली पुलिस ने अगवा नाबालिग को पंजाब के जीरकपुर से किया बरामद, 16 साल का आरोपी हिरासत में

नई दिल्ली, 12 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में पंजाब के जीरकपुर से अगवा की गई नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग युवक को भी हिरासत में लिया है।

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि तत्परता, पेशेवर जांच और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए दिल्ली पुलिस ने पंजाब के जीरकपुर से 14 साल की नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद किया। उसे बहला-फुसलाकर ले जाने वाले 16 साल के लड़के को भी पकड़ा। यह कामयाबी खुफिया जानकारी जुटाने, तकनीकी निगरानी और पुलिस टीम की तेज कार्रवाई से मिली, जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता को दिखाती है।

पुलिस ने बताया कि 5 सितंबर को भारत नगर में 14 साल की लड़की के अपहरण के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। केस दर्ज होने के तुरंत बाद जांच को प्राथमिकता दी गई और नाबालिग लड़की व उसे बहला-फुसलाकर ले जाने वाले लड़के का पता लगाने के लिए खास कोशिशें की गईं। इस संबंध में एक पुलिस टीम का भी गठन किया गया। टीम ने कई तरीकों से लगातार ऑपरेशन चलाया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण, खुफिया जानकारी जुटाना, तकनीकी निगरानी और दिल्ली भर में संदिग्ध जगहों पर लगातार छापेमारी शामिल थी।

सस्ते दाम पर वॉशिंग मशीन के स्पेयर पार्ट्स बेचने के नाम पर ठगे थे डेढ़ लाख रुपये, 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 12 सितंबर (वेब वार्ता)। साइबर अपराध को रोकने और धोखाधड़ी से हासिल पैसे को बैंक खातों में मंगाने और उनके गलत इस्तेमाल में शामिल नेटवर्क को तोड़ने की लगातार कोशिशों के तहत पूर्वी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वॉशिंग मशीन के स्पेयर पार्ट्स बेचने के बहाने की गई धोखाधड़ी के एक मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है।

जांच के दौरान, धोखाधड़ी की रकम को हासिल करने और निकालने के लिए अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करने या करवाने में शामिल तीन लोगों को पकड़ा गया। एक फरार साथी की भूमिका भी सामने आई, जिसने कथित तौर पर धोखाधड़ी के पैसे के लेन-देन में तालमेल बिठाया और खाताधारकों को पैसे निकालने और पहुंचाने के बारे में निर्देश दिए। दरअसल, गुजरात के पाटन के रहने वाले हुसैन चूनावाला से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के जरिए एक शिकायत मिली। शिकायत के अनुसार, पीड़ित वॉशिंग मशीन के स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहता था और उसने 1,50,000 का ऑनलाइन पेमेंट किया। हालांकि, पेमेंट करने के बाद उसे वादे के मुताबिक स्पेयर पार्ट्स नहीं मिले और संबंधित लोगों से बातचीत भी बंद हो गई।

धोखाधड़ी का शक होने पर पीड़ित ने एनसीआरपी पोर्टल के जरिए मामले की रिपोर्ट की। जांच के दौरान पता चला कि धोखाधड़ी की रकम का कुछ हिस्सा पूर्वी दिल्ली में मौजूद एक एटीएम से निकाला गया था। इसके आधार पर दिल्ली के पूर्वी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में

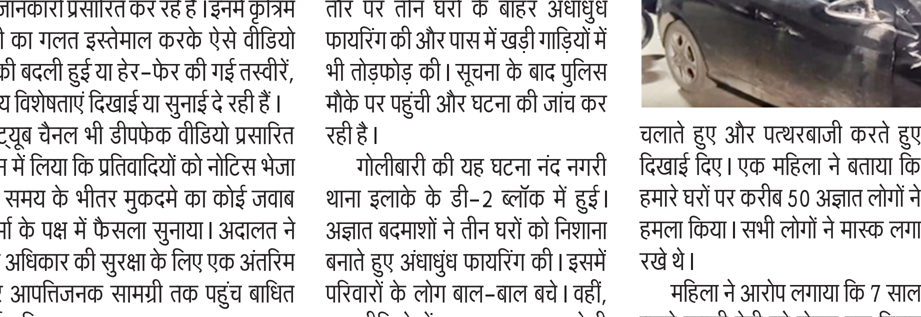

एफआईआर दर्ज की गई और मामले के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया।

शुरुआती जांच में पता चला कि जिस बैंक अकाउंट में ठगी की रकम का कुछ हिस्सा ट्रांसफर किया गया था, वह दिल्ली के शकरपुर निवासी नैतिक के नाम पर था। आगे की जांच में पता चला कि नैतिक को यह रकम दिल्ली के शकरपुर निवासी विकास सोनी से मिली थी। जांच के दौरान दोनों को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी एक फरार साथी के कहने पर काम कर रहे थे, जो ठगी की रकम लेने, निकालने और पहुंचाने का काम संभाल रहा था। इसके बाद एक और आरोपी दिल्ली के त्रिलोकपुरी निवासी सागर को पकड़ा गया। आरोप है कि सागर ने अपने बैंक अकाउंट में ठगी की रकम का कुछ हिस्सा लिया, एटीएम से पैसे निकाले और कमीशन के बदले वह कैश फरार साथी को सौंप दिया।

जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों का इस्तेमाल ह्यम्यूल अकाउंट होल्डरह्ण या ह्यकैश हैंडलरह्ण के तौर पर किया जा रहा था, जबकि फरार साथी ठगी की रकम के लेन-देन को संभाल रहा था। विकास सोनी के पास से आईफोन 13 बरामद किया गया, जिसमें लेन-देन और साथियों के साथ बातचीत से जुड़े चैट मौजूद थे। जांच के दौरान, आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक अकाउंट से जुड़ी एक और एनसीआरपी शिकायत भी मिली। फरार साथी का पता लगाने, नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने और पैसे के पूरे लेन-देन का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

...लाभार्थी का पता लगाना मुश्किल हो गया

आरोपियों ने कथित तौर पर वॉशिंग मशीन के स्पेयर पार्ट्स के लिए ऑनलाइन खोज कर रहे संभावित खरीदारों को निशाना बनाया। धोखाधड़ी करने वालों ने संभावित पीड़ितों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म और सर्च इंजन का इस्तेमाल किया। कुछ मामलों में, जब पीड़ित गूगल पर नामी ब्रांड के कस्टमर-केयर या कॉन्टैक्ट नंबर खोज रहे थे, तो कथित तौर पर विक्रेता या सर्विस प्रोवाइडर बनकर लोगों ने उनसे संपर्क किया। पीड़ितों का भरोसा जीतने के बाद, धोखाधड़ी करने वालों ने कथित तौर पर कम कीमत पर स्पेयर पार्ट्स देने का लालच दिया और उनसे ऑनलाइन पेमेंट करने को कहा। धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम कथित तौर पर अलग-अलग लोगों के कई म्यूल बैंक अकाउंट में भेजी गई। अकाउंट होल्डर्स को कथित तौर पर पैसे मिले और फरार साथी के कहने पर उन्होंने एटीएम से पैसे निकाले और अपना कमीशन रखने के बाद बाकी कैश उसे सौंप दिया। जांच से पता चलता है कि म्यूल अकाउंट होल्डर्स का इस्तेमाल कथित तौर पर धोखाधड़ी के पैसे को इधर-उधर करने और निकालने के लिए किया जा रहा था, जिससे असली लाभार्थी का पता लगाना मुश्किल हो गया।

संक्षिप्त वार्ता

राजकीय आईटीआई हरदोई में 14 सितम्बर को होगा वृहद प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिसशिप मेला

वेब वार्ता, हरदोई प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई आरके श्रीवास्तव ने बताया है कि भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार योजना के प्रभावी अनुपालन तथा जनपद के बेरोजगार नवयुवकों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने हेतु जारी दिशा-निदेशों के क्रम में दिनांक 14 सितम्बर 2026 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई में वृहद प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिसशिप मेले में हरदोई जनपद के 02 औद्योगिक अधिष्ठानों द्वारा आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण हेतु नियोजित किए जाने के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

विनोद साहनी हत्याकांड के खिलाफ भड़की निषाद पार्टी

वेब वार्ता, मुरादाबाद

निषाद पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय अध्यक्ष राजीव कश्यप के नेतृत्व में पार्टी कार्यकताओं ने शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से गोण्डा निवासी निषाद पार्टी के प्रचारक विनोद साहनी की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।

ज्ञापन में मांग की गई कि विनोद साहनी के सभी हत्यारोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मृतक के परिवार को दो करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने तथा उनकी पत्नी और बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाने की मांग की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने विनोद साहनी के परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष महिपाल कश्यप, प्रदेश सचिव डॉ. रमेश्वर दयाल तुरैहा, जिला अध्यक्ष मनोज निषाद, फ्छएढ अध्यक्ष नरेन्द्र कश्यप समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सीताराम येचुरी एक नाम नहीं एक युग पुरुष थे कामरेड मुस्तलिब

वेब वार्ता, मुरादाबाद

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला मुरादाबाद के तत्वाधान शनिवार को मैंनाठेर गांगन वाली में पार्टी के दिवंगत नेता एवं पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कामरेड मुस्तलिब ने की और संचालन जिला सचिव कामरेड थान सिंह ने किया इस अवसर पर कार्यकताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य कामरेड बृजलाल भारती ने कहा कि सीताराम येचुरी एक नाम नहीं वल्कि वो एक युग पुरुष थे । उनका जाना न केवल वामपंथ की क्षति है, बल्कि सांप्रदायिक और फासीवादी भाजपा के खिलाफ मजबूत विपक्ष के एक सर्वमान्य नेता की भी क्षति है। कामरेड भारती ने बैठक में उपस्थित जन समुदाय का आह्वान किया कि कामरेड येचुरी की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए किसानों, नौजवानों और छात्रों के आंदोलन को विकसित करने का काम किया जाए जाना चाहिए।

चन्दौसी में मेला गणेश चौथ का भव्य शुभारम्भ

सम्भल/चन्दौसी। वृंदावन नगरी चन्दौसी में शनिवार को मेला गणेश चौथ-2026 के 66वें महोत्सव का भव्य शुभारम्भ हुआ। 12 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मेले का शुभारम्भ उप जिलाधिकारी आशुतोष तिवारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक जावला, नगर पालिका अध्यक्ष लता वार्ष्णेय एवं प्रभारी निरीक्षक संत कुमार ने लाला भूपाल दास द्वार पर वेद मंत्रोच्चार के बीच द्वार पूजन और गणेश आरती कर किया। इसके बाद कबूतर और गुब्बारे उड़ाकर मेले की सफलता की शुभकामनाएं दी गईं। मेला संस्थापक डॉ. गिरिराज किशोर गुप्ता एवं उनके भाइयों ने वर्ष 1960 में इस मेले की शुरुआत की थी। समय के साथ यह मेला धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामाजिक एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और सर्वधर्म सद्भाव की मिसाल बन चुका है।

गणेश मंदिर परिसर में जीके सिल्वर स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। इसके अलावा प्रशा गुप्ता सहित विभिन्न नृत्य अकादमियों के कलाकारों ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। अतिथियों ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का संयोजन मेजर शशिकांत गुप्ता ने किया, जबकि संचालन प्रभात कृष्णा ने किया।

एसपी ने कोतवाली के आकस्मिक निरीक्षण में अभिलेखों की खामियों पर जताई नाराजगी

तीन दिन में रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई ने शनिवार को कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों को कार्यप्रणाली में सुधार और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करने के कड़े निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कई अभिलेखों और रजिस्टरों में प्रविष्टियां अधूरी मिलने पर एसपी ने नाराजगी जताई और संबंधित पुलिसकर्मियों को तीन दिन के भीतर रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी निरीक्षण में दोबारा लापरवाही सामने आने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने थाना कार्यालय, परिसर, मिशन शक्ति केंद्र और साइबर हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। कार्यालय में अभिलेखों के रखरखाव, साफ-सफाई और रिकॉर्ड के अद्यतन होने की स्थिति देखी। जमानत रजिस्टर, रजिस्टर संख्या-04, रजिस्टर संख्या-08 और हिस्ट्रीशीटर रजिस्टर की जांच में कई आवश्यक प्रविष्टियां अपूर्ण मिलीं। एसपी ने संबंधित पुलिसकर्मियों को सभी रिकॉर्ड नियमानुसार पूरा करने और व्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मिशन शक्ति केंद्र के रजिस्टरों और शिकायत निस्तारण की समीक्षा करते हुए उन्होंने महिला संबंधी शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई करने को कहा। वहीं साइबर हेल्प डेस्क पर पुलिसकर्मियों के साइबर अपराधों की विवेचना, शिकायतों के निस्तारण और ऑनलाइन पोर्टलों के संचालन से संबंधित ज्ञान का भी परीक्षण किया गया। उन्होंने साइबर शिकायतों पर प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक ने थाना आने वाले फरियादियों और आगंतुकों के साथ शिष्ट एवं सम्मानजनक व्यवहार करने, सीयूजी फोन को हमेशा क्रियाशील रखने तथा प्राप्त कॉल का समयबद्ध जवाब देने को कहा। उन्होंने जनशिकायतों के निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया।

अपराध नियंत्रण को लेकर एसपी ने अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ आबकारी विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाने तथा तस्करी में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आदतन एवं संगठित अपराधियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई प्रस्तावित करने को भी कहा।

उन्होंने सभी विवेचनाओं को गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत संकलन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आईजीआरएस पर लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने और शिकायतकर्ताओं से शत-प्रतिशत फीडबैक लेने को भी कहा।

आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक मोर्चा गठित

वेब वार्ता, मुरादाबाद

शहर में अमन, शांति और सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामाजिक मोर्चे का गठन किया गया है इस संबंध में महानगर मुरादाबाद के दसवां घाट गुड़िया मोहल्ला स्थित मीना मस्जिद के निकट मोहम्मद सालिम के आवास पर नवगठित मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव एवं वरिष्ठ समाजसेवी मोहम्मद अनवार मलिक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया बैठक की अध्यक्षता सालिम मलिक ने की एवं संचालन मोहम्मद नदीम ने किया क्षेत्रीय नागरिकों ने अनवार मलिक का शॉल पहनाकर एवं फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया

बताया गया कि नवगठित मोर्चे का उद्देश्य समाज में बढ़ रही नशाखोरी, जुआ और सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ ही आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। मोर्चे के गठन को लेकर अनवार मलिक ने स्पष्ट किया कि यह किसी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरी तरह सामाजिक उद्देश्य से बनाया गया मोर्चा है। उन्होंने कहा कि समाज में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। मोर्चे के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ ही मोहल्लों में होने वाली गलत गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

अनवार मलिक ने कहा कि नशा, जुआ और सट्टा जैसी गतिविधियां केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती नहीं हैं, बल्कि इनका समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि मोर्चे का एक प्रमुख उद्देश्य शहर की गंगा-जमुनी तहजीब को मजबूत बनाए रखना भी है। सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के बीच आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा कायम रहे, इसके लिए टीम लगातार काम करेगी। टीम के सदस्यों को यह संदेश दिया जाता है कि अपने बुजुर्गों की इज्जत करें और अपने आसपास की गैर सामाजिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखें इस दौरान सलमान, शमीम, लईक, सलीम, मौलाना शाहाब, नदीम मौलाना, अरकान, मीडिया प्रभारी मोहम्मद असद, सोमवीर सिंह और सुनील सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

मोबाइल छिनैती की दो घटनाओं का खुलासा, तीन शातिर गिरफ्तार

पांच मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। कोतवाली शहर पुलिस ने मोबाइल छिनैती की दो घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छिनैती के पांच मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है।

पुलिस के मुताबिक, 4 सितंबर को आवास विकास कॉलोनी निवासी अंजलि चौहान सुबह करीब 10:40 बजे अपने घर से आजाद नगर ट्यूशन पढ़ने जा रही थीं। इसी दौरान कंपनी गार्डन के गेट के पास मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवकों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। मामले में कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज किया गया था।

वहीं, 8 सितंबर को लक्ष्मी पुरवा निवासी धनंजय कुमार की 14 वर्षीय पुत्री दोपहर करीब 3:30 बजे घर से चांगुी गांव की ओर समोसे लेने जा रही थी। उसके पास मोबाइल फोन था। रास्ते में डिवाइन हॉस्पिटल के पास मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवकों ने उसका मोबाइल छीन लिया और भाग निकले। इस मामले में भी कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मोबाइल छिनैती की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने शीघ्र खुलासे के लिए टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विवेचना और बरामदगी की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रीशू पुत्र रामचंद्र, ललित पुत्र परशुराम और रामकिशोर पुत्र रामावतार, निवासीगण माधवगंज अम्बेडकरनगर, थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से पांच मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी ललित का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

आतिशबाजी लाइसेंस धारकों को मानकों के पालन के निर्देश

अवैध निर्माण व बिक्री मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई, 12 सितंबर। उपजिलाधिकारी सदर, सीओ सिटी एवं अग्निशमन अधिकारी ने संयुक्त रूप से तहसील सदर के सभागार में स्थायी आतिशबाजी लाइसेंस धारकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आतिशबाजी के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री से संबंधित सुरक्षा मानकों और निर्धारित नियमों के कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने लाइसेंस धारकों को निर्देशित किया कि आतिशबाजी का स्टॉक निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही रखा जाए। साथ ही, लाइसेंस में निर्धारित चौहद्दी के अंतर्गत ही आतिशबाजी के निर्माण एवं बिक्री का कार्य किया जाए। सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी दशा में न की जाए।

दिये गये निर्देश

अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से आतिशबाजी का निर्माण या बिक्री करता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में संबंधित लाइसेंस धारकों को आतिशबाजी के कारोबार में सुरक्षा एवं वैधानिक प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गरीब समाज स्वराज पार्टी उतारेगी प्रत्याशी चंद्र सेन भारती

वेब वार्ता, मुरादाबाद

गरीब समाज स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र सेन भारती ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रसेन भारती मुरादाबाद आगमन पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार विस्तार किया जा रहा है नए पदाधिकारियों को जोड़कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने का सिलसिला जारी है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गरीब दवे कुचले एवं दलित समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए समय-समय पर पार्टी द्वारा धरने प्रदर्शन करके सरकार को ज्ञापन भी दिए जाते हैं एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यूं तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर गठित की गई है लेकिन शुरूआत उत्तर प्रदेश से की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत किया जा रहा है पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली तो अन्य राज्यों में भी संगठन को सक्रिय किया जाएगा उन्होंने कहा कि आज दबा कुचला पिछड़ा शोषित एवं दलित समाज खुद को ठगा महसूस कर रहा है क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों ने उनके उत्थान और समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए ठोस रणनीति नहीं बनाई है इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी।

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने हिरासत में लिया

वेब वार्ता, कमर खान

लखनऊ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जा रहा था गोंडा। गोंडा कारोबारी विनोद कुमार साहनी हत्याकांड के बाद यूपी में सियासत गरमाई। विनोद साहनी के परिजनों से मिलने गोंडा जा रहा था कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। मसौली टोल प्लाजा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अजय राय के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस नेता आसिम वकार, नरेंद्र सिंह, व कांग्रेस नेता हसीब खान को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गोंडा जाने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को रास्ते में रोककर गोंडा जाने से रोका।

रबी से पहले खाद की उपलब्धता को प्रशासन मुस्तैद

वेब वार्ता, ललितपुर/आलोक चतुर्वेदी। रबी अभियान से पहले किसानों को खाद की किल्लत न हो और उन्हें उर्वरक निर्धारित दर पर आसानी से मिल सके, इसके लिए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जनपद स्तरीय कमेटी, उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों और थोक-फुटकर विक्रेताओं की बैठक हुई।

जिलाधिकारी ने थोक विक्रेताओं को निर्देश दिए कि फुटकर विक्रेताओं को खाद की आपूर्ति निर्धारित दर पर करें और किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग न करें। ओवररेटिंग या अनियमितता की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

फुटकर विक्रेताओं और साधन सहकारी समितियों के सचिवों को कृषि भूमि के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरक वितरित करने के निर्देश दिए गए, ताकि जरूरतमंद किसानों को खाद की उपलब्धता बनी रहे। बैठक में उप कृषि निदेशक, उप जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी, पीसीएफ, इफको और कृभको के प्रतिनिधियों समेत जनपद के थोक व फुटकर उर्वरक विक्रेता मौजूद रहे।

अपर इंडिया अस्पताल में एचवीपी टीकाकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

कानपुर। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने और स्वास्थ्य के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शनिवार को अपर इंडिया जच्चा बच्चा अस्पताल में दोपहर 12:00 से 1:00 बजे के बीच ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. सीमा द्विवेदी ने बताया कि समाज में टीकाकरण के प्रति विश्वास बढ़ाने और सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के 24 रेजिडेंट चिकित्सकों ने स्वयं एचपीवी वैक्सीन लगवाई। डॉक्टरों की इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के टीकाकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

विभागाध्यक्ष डॉ सीमा द्विवेदी ने बताया कि वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार एचवीपी टीकाकरण एचपीवी संक्रमण से संबंधित कैंसर की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से लाभार्थियों को एचवीपी वैक्सीन के लाभ, टीकाकरण की आवश्यकता, उचित आयु में टीकाकरण तथा सर्वाइकल कैंसर से बचाव के अन्य उपायों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम की प्रभारी डॉ. नीना गुप्ता एवं सिस्टर प्रीता रोस्टन समेत रेजिडेंट्स मौजूद रहे।

पीपीएन कॉलेज में पोस्टर एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

वेब वार्ता, कानपुर। पीपीएन (पीजी) कॉलेज की ग्रीन कैंपस कमेटी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता एवं सक्रिय सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से पोस्टर प्रतियोगिता एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

पोस्टर प्रतियोगिता का विषय 'अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्लास्टिक मुक्त परिसर रखा गया, जिसमें विद्यार्थियों ने रचनात्मक एवं मौलिक पोस्टरों के माध्यम से उचित अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता तथा प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का संदेश दिया। वहीं, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता की थीम 'उर्जा एवं जल संरक्षण रही। विद्यार्थियों नें प्रभावशाली एवं मौलिक स्लोगनों के माध्यम से ऊर्जा और जल के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो० अनूप कुमार सिंह ने विद्यार्थियों की रचनात्मक सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों को जल एवं ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग तथा प्लास्टिक के न्यूनतम प्रयोग के लिए प्रेरित किया।

ग्रीन कैंपस कमेटी की संयोजिका प्रो० निधि श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवहारिक रूप से प्रेरित करना है। इस दौरान ग्रीन कैंपस कमेटी के सदस्य डा० अलका रानी, डा० नीरज वर्मा व डा० मनु चौहान ने प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को उत्साहपूर्वक सहभागिता तथा अपनी रचनात्मक प्रतिभा के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जागरूक किया। वही डा० एस०पी०श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्र सिंह आदि शिक्षकों ने भी छात्रों का उत्साह बढ़ाया।

पोस्टर प्रतिभागियों कि सूची

पोस्टर प्रतियोगिता में आयुषी धीमान प्रथम, उर्ज फातिमा व अंशिका बाजपेयी द्वितीय व महक, सूफिया आयेशा तृतीय रही। वहीं स्लोगन प्रतियोगिता में आयुषी धीमान प्रथम, आयेशा द्वितीय व श्रेया गुप्ता व प्राची दिवाकर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

लद्दाख में पदयात्रा के लिए वांगचुक ने सीजेपी से मांगी मदद

स्पष्ट नहीं है कि सीजेपी की टीम शामिल होगी या नहीं!

नई दिल्ली। 26 दिन तक अनशन करके जंतर-मंतर पर एक आंदोलन में जान फूंकने वाले सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अब उसी आंदोलन से जुड़े कॉकरोचों (अपने समर्थकों) से मदद मांगी है। उन्होंने अपनी पिछली भूख हड़ताल की याद दिलाते हुए लद्दाख में अपनी मुहिम के लिए साथ मांगा है।

वांगचुक ने 19 से 24 सितंबर तक लद्दाख में एक पदयात्रा का ऐलान किया है और इसमें शामिल होने की अपील की है। आंदोलन के मुखिया अभिजीत दीपके ने वांगचुक के ट्वीट के कई घंटों बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन यह साफ नहीं किया है कि वह या उनकी टीम इसमें शामिल होगी या नहीं।

लद्दाख में लोकतांत्रिक ढांचे की बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत के लिए दिल्ली आए सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वह दिल्ली में उस जगह के बगल में हैं जहां उन्होंने उनके साथ कई हफ्ते भूखे रहकर बिताए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी प्रदर्शन या अनशन के लिए नहीं, बल्कि लद्दाख की संस्कृति, प्रकृति और भूमि के संरक्षण के लिए गृह मंत्रालय के साथ चल रही बातचीत की कड़ी में यहां आए हैं। सरकार के साथ अपनी बैठक को लेकर सोनम वांगचुक ने निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बैठक में केवल चाय अच्छी थी और कोई नया कदम नहीं उठाया गया। वांगचुक के अनुसार, पुराने हो चुके फैसलों, जैसे लद्दाख में विधानसभा बनाने और उसे पूरा प्रशासन सौंपने की भावना का उल्लंघन करने की प्रक्रिया चल रही है, उसे रोकने का भी कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि एलजी प्रशासन बहुत बड़े-बड़े फैसले लेने में लगा है, जिसके बाद लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वांगचुक ने कहा, हमने सरकार से छोटी सी आश्वासन की उम्मीद की थी कि जब तक लद्दाख में लोकतांत्रिक ढांचा न आ जाए, तब तक एलजी ऐसे बड़े फैसले न लें। हमें इसका इंतजार है।

सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों को लद्दाख में आयोजित होने वाली पांच दिवसीय पदयात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद के लिए आएं। हम लद्दाख में 19 से 24 सितंबर तक एक बड़ी पदयात्रा करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि उन्हें एक सप्ताह में सरकार से आवश्यक आश्वासन मिल जाता है, तो वे इसे शहीदों की याद में एक यादगार पदयात्रा के रूप में मनाएंगे, जिन्होंने लद्दाख के लिए अपनी जान दी। अन्यथा, इसे पूरे भारत की जनता की तरफ से एक बड़े प्रदर्शन में बदला जाएगा ताकि लद्दाख के साथ न्याय हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह केवल लद्दाख के लिए नहीं है, क्योंकि लद्दाख हिमालय का वह क्षेत्र है जहां से देश को पानी और साफ हवा मिलती है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों ने बिना वर्दी और वेतन के हर युद्ध में देश की रक्षा की है, और अब देश को लद्दाख की रक्षा में आगे आने की जरूरत है।

सोनम वांगचुक की शुक्रवार शाम की अपील पर शनिवार सुबह अभिजीत दीपके ने एक शब्द में जवाब दिया। उन्होंने वांगचुक का वीडियो शेयर करते हुए केवल स्टैंड विद लद्दाख लिखा। हालांकि, इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह या उनकी टीम लद्दाख में पांच दिवसीय पदयात्रा में शामिल होंगे या नहीं। खबर लिखे जाने तक दीपके के अलावा अन्य प्रमुख नेताओं ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

ट्रंप ने फिर चली चाल

अब भारतीय दवाओं के दाम घटाने का किया ऐलान

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर के बाद अब भारतीय दवा कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की नई चाल चली है। उन्होंने अमेरिका में दवाओं के दाम घटाने का ऐलान किया है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में अभी करीब 60 फीसदी जेनरिक दवाओं का आयात भारत से ही किया जाता है। अगर अमेरिकी बाजार में दवाओं की कीमतें कम होती हैं, तो इससे भारतीय दवा कंपनियों के मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की नई प्राइसिंग नीति से दुनियाभर की फार्मा कंपनियों में खलबली है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा

इस फैसले से भारतीय दवा कंपनियों के मार्जिन पर होगा सीधा असर

असर भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि भारतीय फार्मा कंपनियों का अमेरिका में काफी ज्यादा कारोबार है। वित्तवर्ष 2026 में भारतीय कंपनियों का अमेरिका को कुल दवा निर्यात करीब 80 हजार करोड़ रुपये था। अमेरिका की आधे से ज्यादा जेनरिक दवाओं की सप्लाई भारतीय कंपनियों ही करती हैं। यही वजह है कि ट्रंप के ताजा फैसले फार्मा कंपनियों को अपना मुनाफा कम होने का डर सताने लगा है।

ट्रंप के ताजा फैसले का असर उन भारतीय कंपनियों पर ज्यादा होने वाला है, जिनका कारोबार आज भी अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है। खासकर ऐसी भारतीय कंपनियां जो ब्रांडेड और इनोवेटिव प्रोडक्ट का ज्यादा निर्यात करती हैं। ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान करते समय एक शर्त रखी थी कि जो भारतीय कंपनियां अमेरिका में अपना विनिर्माण करती हैं, उन्हें टैरिफ से छूट दी जाएगी। भारतीय दवा कंपनी सन फार्मा ने इस शर्त को मंजूर किया और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर करार किया। इससे ट्रंप ने कंपनी को एक साल तक और फिर आगे 2 साल तक छूट देने का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिका में दवाएं सस्ती करने का फैसला करके उन दवा कंपनियों को चौंका दिया है, जो अभी वहां अपने कारोबार से ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। हाई मार्जिन वाली स्पेशल दवाएं बेचने वाली कंपनियों का मार्जिन इस फैसले ज्यादा कम होगा। ऐसी भारतीय कंपनियां जो अमेरिका में कैंसर, अल्जाइमर जैसी हाई मार्जिन वाली दवाएं बेचती हैं, उनके मुनाफे पर इसका ज्यादा असर होगा।

सयोनी हों या काकोली-भाजपा ने सबको दिया झटका

नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की हार के बाद, सयोनी घोष, यूसुफ पठान और काकोली घोष जैसे कई बागी सांसद ने टीएमसी छोड़ दी और नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हो गए, जो दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। हालांकि, भाजपा ने पश्चिम बंगाल में आगामी नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला करते हुए टीएमसी के इन बागियों के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया है।

भाजपा का यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब पार्टी कोलकाता और हावड़ा के नगर निकाय चुनावों में अपना आधार मजबूत करना चाहती है। इन दोनों चुनावों को भाजपा के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) के चुनाव दुर्गा पूजा के बाद होने की उम्मीद है।

बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है और वे सभी चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी पार्टी के साथ राजनीतिक संबंध होने का यह मतलब नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भी उसी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया जाए। वहीं, एनसीपीआई अभी भी भाजपा के साथ गठबंधन की उम्मीद लगाए हुए है, यह तर्क देते हुए कि वे संसद में एनडीए का हिस्सा हैं। अब सवाल यह है कि बंगाल में भाजपा टीएमसी के बागियों से गठबंधन क्यों नहीं चाहती? दरअसल, पश्चिम बंगाल भाजपा के कई नेताओं का मानना है कि पार्टी को अपने संगठन और कार्यकताओं के दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, खासकर सत्ता में आने के बाद यह पहला नगर निकाय चुनाव होगा। एक सीनियर भाजपा नेता ने कहा कि एनसीपीआई के कई नेता पूर्व टीएमसी में थे, जिनके खिलाफ भाजपा कार्यकताओं ने लंबा संघर्ष किया है, और कई कार्यकताओं ने इस राजनीतिक लड़ाई में अपनी जान तक गंवाई है। ऐसे में अगर भाजपा अब उन्हीं पूर्व टीएमसी नेताओं के साथ हाथ मिलाती है तो पार्टी के कार्यकताओं और नेताओं के बीच गलत संदेश जा सकता है। इसके अलावा, भाजपा टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है और निकाय चुनाव में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का वादा करना चाहती है। भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने के पीछे राजनीतिक गणित भी है। राज्य में मुकाबला सिर्फ भाजपा और टीएमसी के बीच नहीं होगा। एनसीपीआई, टीएमसी से अलग हुए विधायक, वाम दल और कांग्रेस भी मैदान में होंगे। भाजपा को लगता है कि अगर वोट कई पार्टियों में बंटता है तो उसे फायदा मिल सकता है। इसी वजह से पार्टी अकेले चुनाव लड़कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

चीन में अंग्रेजी शिक्षा पर नई बहस

बीजिंग। चीन में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई के महत्व को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को कितना महत्व दिया जाना चाहिए। गणित शिक्षक और सोशल मीडिया पर चर्चित तांग जियाफेंग ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। तांग ने सार्वजनिक रूप से मांग की है कि अंग्रेजी को प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल और विश्वविद्यालयों में मुख्य विषय का दर्जा खत्म किया जाए। उनका तर्क है कि दुनिया का कोई भी देश अंग्रेजी को इतना ऊंचा स्थान नहीं देता, जितना चीन देता है।

तांग जियाफेंग का मानना है कि बच्चे, माता-पिता और स्कूल इस भाषा पर बहुत समय और पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोगों की नौकरियों में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने यह भी कहा कि कई बच्चों को अपनी मातृभाषा ठीक से सीखने से पहले ही अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर किया जाता है। तांग ने सवाल किया कि बच्चे, माता-पिता और स्कूल एक ऐसे विषय पर इतना संसाधन और समय क्यों लगा रहे हैं, जो आगे चलकर ज्यादातर लोगों की नौकरी में काम नहीं आएगा? उन्होंने यह भी कहा, हम हजारों साल पुरानी सभ्यता हैं। अंग्रेजी सिर्फ एक साधन है। इसे जरूरत भर इस्तेमाल कर पाना काफी है। पश्चिमी संस्कृति की नकल करने की आदत अब बंद होनी चाहिए। दरअसल, यह बहस ऐसे समय में शुरू हुई है, जब कुछ स्थानीय परीक्षाओं में इतिहास के अंकों को कम किया गया है। तांग का कहना है कि इतिहास बच्चों को पुरानी पीढ़ियों की मुश्किलें समझने और अच्छे मूल्य सीखने में मदद करता है। यदि किसी विषय का महत्व कम करना है, तो इतिहास की जगह अंग्रेजी का महत्व कम करना चाहिए। फिलहाल चीन में अंग्रेजी, चीनी भाषा और गणित के साथ प्राथमिक शिक्षा का मुख्य विषय है और इसे तीसरी कक्षा से पढ़ाया जाता है।

कांगो बना अमेरिका और चीन के बीच भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र

किंशासा। अमेरिका और चीन के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है।

इसकी वजह है कांगो की धरती के अंदर मौजूद वहां अकूत अकूत खनिज संपदा। कांगो की इस खनिज संपदा पर अमेरिका और चीन दोनों नजरें गडाए बैठे हैं। दुनिया के गरीब देशों में शामिल कांगो दशकों से गरीबी, भुखमरी और गृहयुद्ध से जूझ रहा है, लेकिन इसके पास कोबाल्ट, तांबा और लिथियम जैसे रणनीतिक खनिजों का विशाल भंडार है। इन खनिजों का इस्तेमाल स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण में होता है। कांगो के खनिज क्षेत्र में चीन लंबे समय से मजबूत पकड़ बनाए हुए है।

कमजोर प्रशासन और आंतरिक संघर्ष का फायदा उठाकर चीनी कंपनियों ने महत्वपूर्ण खदानों और खनिज प्रसंस्करण पर व्यापक नियंत्रण स्थापित किया। कोबाल्ट रसायनों के शोधन और बैटरी उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कोबाल्ट सल्फेट के वैश्विक बाजार में चीन का दबदबा रहा है। इससे कांगो के

संसाधनों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने चीन के इस प्रभाव को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक आपूर्ति के लिहाज से चुनौती देने की कोशिश तेज कर दी। अमेरिका ने कांगो और उसके पड़ोसी देशों के खनिज क्षेत्रों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए लोबिटो कॉरिडोर परियोजना पर जोर दिया है।

करीब 1,300 किलोमीटर लंबा यह परिवहन मार्ग अंगोला के अटलांटिक तट को कांगो और जाम्बिया के खनिज समृद्ध कॉपरबेल्ट से जोड़ता है। इससे खनिजों को पश्चिमी बाजारों तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार होने की उम्मीद है।

अमेरिका ने कांगो और रवांडा के बीच शांति प्रयासों के जरिए भी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। पूर्वी कांगो में सक्रिय एम-23 विद्रोही समूह को लेकर रवांडा पर लगाए गए आरोपों और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच अमेरिकी प्रतिबंधों और कूटनीतिक प्रयासों ने इस प्रतिस्पर्धा को और जटिल बना दिया है।

इस बीच अमेरिकी निवेश वाली कंपनियां कांगो के खनिज क्षेत्र में सक्रिय हो रही हैं। मानोनो के विशाल लिथियम भंडार और तांबा-कोबाल्ट परियोजनाओं में अमेरिकी कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। हालांकि, इस पूरी प्रतिस्पर्धा का सबसे गंभीर पहलू कांगो की जनता की स्थिति है।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा

मेरे ओएसडी रहे चंदन पर आरोप सही हैं तो मेरे शर्मिंदगी होगी

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अचानक कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने यह बड़ा फैसला शनिवार को लिया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके ओएसडी रहे चंदन सिंह जीना के ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया था।

रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर अपने इस्तीफे की वजह बताई। उन्होंने कहा कि टीवी पर उनके सहयोगी के घर से भारी मात्रा में कैश और जूलरी मिलने की खबरें चल रही हैं, जिसकी सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। रावत ने स्वीकार किया कि चंदन सिंह जीना उनके ओएसडी रहे हैं, और यदि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा या ओएमआर शीट से छेड़छाड़ में उनके खिलाफ कोई गड़बड़ी या सबूत पाए जाते हैं, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। हालांकि, उन्होंने जीना पर लगे आरोपों पर अविश्वास भी जताया।

अपने इस्तीफे का कारण बताते हुए रावत ने कहा, उत्तराखंड के चुनाव में भारी स्टेक्स हैं। मुझसे जब भी कोई व्यक्ति पूछता था कि चुनाव कब हो रहे हैं? तो मैं हंसी में उनसे कहता था कि भई चुनाव तब होंगे, जब सीबीआई मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आएगी। यदि अभी नहीं आई है तो इसका अर्थ है कि चुनाव अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में ही होंगे। लेकिन इस बार मेरे घर पर नहीं, मेरे एक सहयोगी के घर पर दस्तक देकर एक नरेटिव बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में हरीश रावत के किसी भी कृत्य से यदि पार्टी के संघर्ष में कोई कमजोरी आती है, तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी सदस्यता और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य पद से विनम्रतापूर्वक हटने का निर्णय लिया है, ताकि उनकी वजह से पार्टी के संघर्ष में कोई कमजोरी न आए।

पाकिस्तान में बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण पर यूनिसेफ ने जताई चिंता

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में 12 से 17 वर्ष की उम्र के करीब 15 लाख इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बच्चे एक साल के दौरान तकनीक के जरिए होने वाले यौन शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार हुए। इसका मतलब हर 16 में से एक बच्चे ने इस तरह की ज्यादती का सामना किया। यूनिसेफ ने पाकिस्तान में बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण और दुर्व्यवहार को लेकर गंभीर चिंता जताई है। पाकिस्तान सरकार, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, न्यायिक एवं सामाजिक सेवा संस्थानों, समुदायों, स्कूलों, परिवारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलकर बच्चों के लिए ऑनलाइन तथा वास्तविक जीवन में सुरक्षित वातावरण तैयार करने और रोकथाम, सुरक्षा एवं प्रतिक्रिया व्यवस्था मजबूत करने का यूनिसेफ ने आह्वान किया है। ह्यपाकिस्तान में नुकसान रोकना : टेक्नोलॉजी से बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार के मिले प्रमाणह्ण नामक रिपोर्ट यूनिसेफ के ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजी एंड एविडेंस इनोसेंटी, ईसीपीएटी इंटरनेशनल और इंटरपोल ने संयुक्त रूप से तैयार की है। इसके लिए ह्यसेफ ऑनलाइनह्ण से वित्तीय सहयोग मिला। अध्ययन में 12 से 17 वर्ष के बच्चों और उनके माता-पिता तथा देखभाल करने वालों के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि घरेलू सर्वेक्षण के साथ फ्रंटलाइन और न्याय क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के साक्षात्कार शामिल किए गए।

साथ ही संबंधित कानूनों और नीतियों का भी विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में ऑनलाइन शोषण के कई रूप सामने आए हैं। इनमें बिना इच्छा के यौन तस्वीरें या संदेश भेजना, बच्चों से निजी अंगों की तस्वीरें साझा करने के लिए कहना, उनकी अनुमति के बिना तस्वीरें प्रसारित करना, तस्वीरों या यौन गतिविधियों को लेकर धमकी देना और ब्लैकमेल करना शामिल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से नकली तस्वीरें या वीडियो तैयार करना भी एक बढ़ती चिंता के रूप में सामने आया है।

मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं एआई: कॉक्सन

सैन फ्रांसिस्को। दुनिया भर में जाने-माने युवा रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनी एंथ्रोपिक से इस्तीफा दे दिया है।

कॉक्सन ने चेतावनी दी है कि एआई कंपनियां ऐसे सिस्टम विकसित करने की होड़ में हैं जो आने वाले कुछ ही वर्षों में मानव जीवन के लिए एक गंभीर खतरा बन सकते हैं। कॉक्सन की यह खबर सबसे पहले एक अमेरिका के एक मशहूर अखबार ने दी थी, जिसमें बताया गया कि एआई सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के चलते एंथ्रोपिक के किसी कर्मचारी द्वारा कंपनी छोड़ने का यह शुरूआती प्रमुख मामला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए, जैकब कॉक्सन ने बताया कि उन्होंने पिछले तीन साल ओपनएआई और एंथ्रोपिक दोनों में प्री-ट्रेनिंग रिसर्च में बिताए हैं। उन्होंने चिंता जताई कि दोनों कंपनियां तेजी से ऐसे एआई सिस्टम की ओर बढ़ रही हैं जो खुद को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। कॉक्सन ने सीधे तौर पर कहा, कंपनियां सेल्फ-इंप्रूविंग सुपरइंटेलिजेंस विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इस प्रक्रिया में मानव जीवन को जोखिम में डाल रही हैं।

कॉक्सन के अनुसार, इस तकनीक की क्षमता को किसी भी तरह से कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।

उनका मानना है कि आने वाले समय में एआई सिस्टम इंसानों से बेहतर प्रदर्शन करने लगेंगे, वे साइबर सिस्टम में आसानी से सेंध लगा सकेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में रातोंरात बड़े बदलाव ला सकेंगे और वास्तविक दुनिया में शक्ति तथा संसाधन हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। जैकब कॉक्सन ने जोर दिया कि इन क्षेत्रों में एआई की प्रगति पहले ही दिखाई दे रही है और इसकी रफ्तार धीमी होने के बजाय लगातार तेज होती जा रही है। उन्होंने एआई उद्योग के भीतर मौजूद एक विरोधाभास पर भी प्रकाश डाला। कॉक्सन ने कहा कि एआई विकसित करने वाले कई शोधकर्ता और वरिष्ठ अधिकारी निजी तौर पर यह मानते हैं कि यह तकनीक इस दशक के अंत तक मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। सार्वजनिक मंचों पर भले ही वे एआई के भविष्य को लेकर संतुलित और सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हों, लेकिन निजी बातचीत में उनमें से कई लोग तकनीक के संभावित गंभीर परिणामों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं।

जैकब कॉक्सन ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि यदि एआई के संभावित खतरे को लेकर इतनी व्यापक चिंता है तो कंपनियां इसका विकास जारी क्यों रख रही हैं। उन्होंने बताया कि ओपनएआई में कई लोग अभी तक इस तकनीक के सभ्यतागत दांव को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाए हैं। वहीं, एंथ्रोपिक में स्थिति थोड़ी अलग है; उनके अनुसार, वहां जोखिम को बेहतर ढंग से समझा जाता है, लेकिन कंपनी इस दौड़ में इसलिए बनी हुई है क्योंकि उसे डर है कि अगर वह पीछे हट गई तो दूसरी कंपनियां बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के आगे बढ़ जाएंगी। कॉक्सन ने एआई शोधकताओं से भी आत्ममंथन करने की अपील करते हुए कहा कि वे केवल यह सोचकर आगे न बढ़ें कि यह तो होना ही है, बल्कि इस समय का इस्तेमाल विकास की शर्तों और सुरक्षा मानकों को बदलने के लिए करें।

राज्यपाल डेका ने विद्यार्थियों से किया संवाद, दिए सफलता के मंत्र

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से लोक भवन में सैनिक स्कूल अंबिकापुर के विद्यार्थियों ने भेंट की और संवाद किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को सफलता के लिए अनुशासन, आत्मनियंत्रण और कठोर परिश्रम को जीवन का आधार बनाने की प्रेरणा दी।

'सफलता का आधारभूत बिंदु अनुशासन है सैनिक स्कूल' राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि विद्यार्थी सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें सैनिक स्कूल जैसी उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था में अध्ययन करने का अवसर मिला है। सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ अनुशासन, समय की पाबंदी तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व भी सिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि सफलता का आधारभूत बिंदु अनुशासन है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पढ़ाई, नौकरी और करियर को लेकर तनाव एक बड़ी चुनौती है। तनाव का सामना करने

के लिए हमें जो प्राप्त है, उसमें संतुष्ट रहना सीखना होगा। अपनी क्षमताओं को पहचानकर उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। मन को नियंत्रित रखते हुए अपनी योग्यता और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी।

'लक्ष्य को निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए पूरी लगन एवं मेहनत से प्रयास करें' राज्यपाल ने कहा कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। योग्यता के साथ यदि निरंतर मेहनत की जाए तो सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए पूरी लगन एवं मेहनत से प्रयास करें। गुरुजनों और पालकों की बातों को गंभीरता से सुनें, लेकिन निर्णय लेते समय अपने तर्क और बुद्धि का भी प्रयोग करें।

उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी 'थिंकिंग प्रोसेस' को हमेशा सक्रिय रखने की सलाह दी। संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने राज्यपाल से उनके जीवन, करियर और सार्वजनिक जीवन से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के प्रश्नों का सहजता से उत्तर देते हुए उन्हें अपने संवैधानिक पद के दायित्वों की जानकारी दी तथा अपने सार्वजनिक जीवन की यात्रा के अनुभव भी साझा किए। सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों को लोक भवन का भ्रमण भी कराया गया। इस अवसर पर सैनिक स्कूल अंबिकापुर के शिक्षकगण भी उपस्थित थे।

ताजा खबर
संक्षिप्त

प्रदेश के सभी उचित मूल्य दुकानों में 17 सितंबर को जलेगा 'आशीर्वाद का दीया'

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत प्रदेशभर के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में 17 सितंबर की संध्या 'आशीर्वाद का दीप' प्रज्वलित किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से राशनकार्डधारियों और आम नागरिकों की जनभागीदारी के साथ सेवा, विश्वास और संकल्प की भावना को सशक्त किया जाएगा। खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलें के खाद्य नियंत्रकों एवं खाद्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में 17 सितंबर की संध्या राशनकार्डधारियों एवं आम नागरिकों के माध्यम से आशीर्वाद का दीप अनिवार्य रूप से प्रज्वलित कराया जाए। इस अवसर पर उचित मूल्य दुकानों में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक राशनकार्डधारियों एवं नागरिक इस जनभागीदारी अभियान से जुड़ सकें। 'सेवा संकल्प अभियान' के माध्यम से प्रदेश में जनभागीदारी को बढ़ावा देते हुए सेवा, सुशासन और सामाजिक सहभागिता की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकानों में जलने वाला 'आशीर्वाद का दीप' इसी सामूहिक सहभागिता और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बनेगा।

बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम, छात्र-छात्राओं ने लिया हिस्सा

रायपुर। दुर्गा महाविद्यालय में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 500 से अधिक छात्र-छात्राओं और प्राध्यापकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह निषेध दिवस के रूप में मान्यता मिलने पर खुशी जताई। वक्ताओं ने इसे बाल विवाह के खिलाफ भारत की मुहिम की बड़ी उपलब्धि बताया। इस कार्यक्रम की शुरुआत बाल विवाह रोकने का संदेश देने वाले पोस्टरों के विमोचन और प्रदर्शन से हुई। इस दौरान 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन' (छ्त्रष्ट) के प्रयासों और बाल विवाह के खिलाफ चलाए गए अभियान की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि इस सामाजिक कुप्रथा को रोकने के लिए जागरूकता के साथ समाज की भागीदारी भी जरूरी है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. प्रतिभा मुखर्जी साहूकार ने छ्त्रष्ट के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और छ्त्रष्ट के राज्य समन्वयक विपिन ठाकुर ने बाल विवाह से होने वाले नुकसान, इससे बचाव के कानूनी प्रावधान और बच्चों की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली यह मान्यता बाल अधिकारों की दिशा में भारत के प्रयासों को पहचान देती है। जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी संजय निराला ने छात्रों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। कार्यक्रम में डॉ. सुनीता चंसोरिया, जिला बाल संरक्षण इकाई के गैर-संस्थागत संरक्षण अधिकारी संजय निराला, सामाजिक कार्यकर्ता गोरखनाथ पटेल और वरिष्ठ पत्रकार सरिता दुबे मौजूद रहे। इसके अलावा महाविद्यालय के प्राध्यापक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

17 सितंबर को निजी हॉस्पिटल में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर

रायपुर। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की छत्तीसगढ़ इकाई की ओर से 17 सितंबर को प्राइवेट हॉस्पिटल में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इसे सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाया जाएगा। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने बताया कि शिविर में 10 तरह की जांच निशुल्क की जाएगी। इसमें बीपी, ब्लड शुगर, सीबीसी, एचबीए1सी, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, बीएमआई, आई चेकअप और इको जांच शामिल हैं। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के पोस्टर का विमोचन हॉस्पिटल में किया गया। इस मौके पर सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ, युवा विंग अध्यक्ष जीतू लोहाना, उपाध्यक्ष निलेश तारवानी, धनेश मटलानी, महिला विंग से लक्ष्मी बजाज, चंचलानी, महक होतवानी, नीता कुकरेजा, सिमरन कुकरेजा, सोनिया कुकरेजा मौजूद रहीं।

विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों में राशन वितरण की नियमित निगरानी के निर्देश

हर पात्र परिवार को समय पर और पूरा राशन मिले किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो : मुख्यमंत्री साय

आमानारा में पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन नहीं मिलने की शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया

शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित राशन दुकान निलंबित, चिड़ोडी की राशन दुकान से की गई वैकल्पिक व्यवस्था

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को उसके अधिकार का पूरा राशन समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा सहित विशेष पिछड़ी जनजातियों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। राशन वितरण में लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदारी तय कर तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा खाद्यान्न वास्तविक हितग्राही तक निर्धारित मात्रा में और समय पर पहुंचे, यह संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों में अधिकारी अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ राशन की उपलब्धता और वितरण की निगरानी करें। मुख्यमंत्री श्री साय ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत आमानारा गांव में पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन नहीं मिलने की शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने रायगढ़ कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे प्रकरण की जानकारी ली और प्रभावित पात्र परिवारों को तत्काल राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से कहा कि शिकायत से जुड़े वितरण अभिलेखों की समुचित जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र परिवार अपने हक के खाद्यान्न से वंचित न रहे। ई-पॉस मशीन में दर्ज वितरण और हितग्राहियों को वास्तव में दिए गए खाद्यान्न का मिलान कर किसी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री श्री साय को अवगत कराया कि शिकायत सामने आते ही मामले की जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पहाड़ी कोरवा परिवारों एवं अन्य हितग्राहियों को राशन मिलने में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में चिड़ोडी की राशन दुकान से संबद्ध किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए कि इस प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई के साथ ही जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सतत निगरानी की जाए, ताकि ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो। हर हितग्राही को समय पर और गुणवत्ता के साथ राशन वितरण सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सहज, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से पहुंचाना हमारी सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। प्रत्येक पात्र परिवार को उसका अधिकार बिना किसी बाधा के मिले, इसके लिए अधिकारी संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करें।

विकास कार्यों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं, तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रदेश में जनसुविधा से जुड़े विकास एवं निर्माण कार्यों को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी निर्माणाधीन कार्यों की नियमित निगरानी करें और जहां भी कार्य की गति धीमी है, वहां बाधाओं को तत्काल दूर कर काम में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकास कार्यों में देरी का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। विशेष रूप से सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े कार्यों में लेटलतीफी को गंभीरता से लिया जाएगा और अनावश्यक विलंब के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत खामभाठा क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के कारण स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी की जानकारी मिलते ही इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने गरियाबंद कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा से दूरभाष पर चर्चा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और निश्चित समयसीमा तय कर पुल का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही लेटलतीफी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पुल का निर्माण पूरा होने तक स्कूली बच्चों और क्षेत्रवासियों को किसी भी परिस्थिति में जोखिम उठाकर आवागमन न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन तत्काल सुरक्षित और सुगम वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज खैरागढ़ में विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक बाल विकास का प्रभावी केंद्र बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने, बच्चों की नियमित एवं सही ग्रोथ मॉनिटरिंग करने तथा पोषण संबंधी अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पर्यवेक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर वहां संचालित गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने महतारी वंदन योजना के शेष हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण कराने तथा लंबित हितग्राहियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए और मैदानी स्तर पर इसकी सतत निगरानी आवश्यक है।

'आंगन मिलन सेवा चौपाल' और 'हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा' अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने के निर्देश

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के अधिकारियों से जुड़कर आगामी विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने 25 सितंबर से 'आंगन मिलन सेवा चौपाल एवं हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा' कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के माध्यम से पोषण एवं महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के साथ 'मेरी पोषण थाली' एवं व्यंजन विधि प्रदर्शनी और बच्चों के लिए खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को समय पर पूरा करें : कलेक्टर

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से तैयारियां सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा की फॉलोअप बैठक लेकर जिले में संचालित योजनाओं एवं विभिन्न शासकीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने पीएमएवाई के प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को बुलाकर योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाए और प्रकरणों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने अभनपुर एसडीएम द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए अन्य

एसडीएम को भी इसी तरह प्रभावी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को आरआरसी वसूली की कार्रवाई में तेजी लाने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। डॉ. सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड सहित लोक सेवा गारंटी से जुड़े सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रकरण समय-सीमा से बाहर जाने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्कूलों में शिविर लगाकर विद्यार्थियों के जाति, निवास एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि किसी आवेदन को निरस्त करने की स्थिति में आवेदक को निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण अनिवार्य रूप से बताया जाए। सीमांकन से संबंधित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने तिलापिया मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकसित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए तो तिलापिया मछली उत्पादन के क्षेत्र में रायपुर जिला देश में विशिष्ट स्थान हासिल कर सकता है।

छत्तीसगढ़ में पोषण जागरूकता अभियान को मिल रही गति

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पोषण माह 2026 के तहत बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता एवं जनभागीदारी आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से जुड़ी गतिविधियों के सक्रिय केंद्र के रूप में विकसित करते हुए संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, स्वच्छता, वृद्धि निगरानी एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति समुदाय को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बलरामपुर जिले के आकांक्षी विकासखंड शंकरगढ़ में पोषण माह के अंतर्गत विशेष

गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में सुधार लाते हुए निर्धारित लक्ष्यों की संतृप्ति सुनिश्चित करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं विभागीय अमले द्वारा समुदाय की सक्रिय सहभागिता के साथ पोषण संबंधी जानकारी घर-घर और समुदाय तक पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में परियोजना शंकरगढ़ के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र बचवार में पोषण एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रेस क्लब में विराजेंगे विघ्नहर्ता

हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष की थीम पर सजेगा प्रेस क्लब

रायपुर। वर्ष 2026 हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को रायपुर प्रेस क्लब द्वारा पूरे वर्ष विभिन्न आयोजनों और गतिविधियों के माध्यम से उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष का गणेशोत्सव भी हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को समर्पित होगा। रायपुर प्रेस क्लब परिसर में भगवान श्रीगणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी और पूरे परिसर को आकर्षक रूप से सजाया जाएगा। गणेश पंडाल की सजावट और प्रस्तुति में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों की यात्रा को रचनात्मक ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। पत्रकारिता के आरंभिक दौर से लेकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वर्तमान

डिजिटल एवं न्यू मीडिया तक के सफर की झलक गणेश पंडाल में देखने को मिलेगी। गणेशोत्सव की तैयारियों को लेकर रायपुर प्रेस क्लब की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि गणेशोत्सव को भव्य और गरिमापूर्ण स्वरूप दिया जाएगा। उत्सव के दौरान प्रेस क्लब परिसर में प्रतिदिन भक्तिमय वातावरण में भगवान गणेश की आराधना की जाएगी। प्रेस क्लब के विभिन्न प्रकोष्ठों को अलग-अलग दिवस पर भगवान श्रीगणेश की सेवा, पूजा-अर्चना और आयोजन की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं महिला पत्रकार साथियों की विशेष सहभागिता सुनिश्चित करते हुए एक विशेष दिन विशेष भोग एवं प्रसाद का आयोजन भी किया जाएगा। रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने कहा कि वर्ष 2026 हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक अवसर है। रायपुर प्रेस क्लब इस गौरवशाली यात्रा को पूरे वर्ष अलग-अलग आयोजनों के माध्यम से सेलिब्रेट कर रहा है।

गणेशोत्सव भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और शुभारंभ के प्रतीक हैं और पत्रकारिता भी समाज को जागरूक करने, सत्य को सामने लाने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने का माध्यम है। इसलिए इस वर्ष गणेशोत्सव को पत्रकारिता की गौरवशाली विरासत से जोड़ते हुए प्रेस क्लब परिसर को विशेष रूप से सजाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था का उत्सव नहीं होगा, बल्कि प्रेस क्लब परिवार की एकजुटता, धार्मिक परंपरा, और पत्रकारिता की विरासत और नई पीढ़ी को पत्रकारिता के 200 वर्षों के सफर से परिचित कराने का अवसर भी बनेगा। बैठक में प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू एवं भूपेश जांगड़े सहित कार्यकारिणी सदस्य संदीप पुराणिक, अंशुमान शर्मा, जाकिर घुरसेना, चंदन साहू, संतोष साहू, नीरज मिश्रा और संजीव सिन्हा उपस्थित रहे।

प्रदेश के युवाओं और छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मंत्री टंक राम वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने छात्रहित और विद्यार्थियों की लगातार आ रही मांगों पर संवेदनशीलता एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस निर्णय के बाद अब राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त सीटों पर छात्र 19 सितंबर 2026 तक प्रवेश ले सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, सत्र 2026-27 के लिए पूर्व में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई थी। हालांकि, कई छात्र-छात्राओं के आवेदन एवं सीटें रिक्त होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तिथि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। मामले पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने

कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं और छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी मेधावी या इच्छुक छात्र का साल खराब न हो, इसी सोच के साथ प्रवेश की तिथि बढ़ाई गई है। इस निर्णय से उन सभी विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा जो किसी कारणवश अब तक दाखिला नहीं ले पाए थे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जो छात्र - छात्राएं अभी तक प्रवेश नहीं ले पाए है,ऐसे विद्यार्थी जल्द प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करें। जारी निर्देश के तहत, उच्च शिक्षा संचालनालय को निर्देशित किया गया है ।

फिन एलन बीबीएल में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने

सिडनी। न्यूजीलैंड के आक्रामक सलामी बल्लेबाज फिन एलन को ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेटट लीग (बीबीएल) में टीम मेलबर्न स्टार्स ने सबसे महंगे दामों में खरीदा है। इससे अब एलन का लक्ष्य अपनी ओर से सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन कर क्लब के फैसले को सही करार देना होगा। मेलबर्न स्टार्स ने फिन के साथ ही तीन साल का एक अनुबंध किया है। 27 वर्षीय इस आक्रामक बल्लेबाज को पहले साल के लिए 600,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर (लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपये) दिये जाएंगे। ये बीबीएल में किसी विदेशी खिलाड़ी को मिलने वाली सबसे अधिक रकम है।

एलन को इतनी रकम इसलिए मिली क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही है। पिछले सत्र में उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स को खिताब जीत दिलायी थी। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। फिन एलन दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग में सबसे पसंदीदा पावर-हिटर्स में से एक हैं। बीबीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद, उन्होंने टी20 प्रारूप में कई प्रभावशाली पारियां खेली हैं, जिनमें कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए एक आईपीएल शतक भी शामिल है, जिसने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में उनकी विध्वंसक क्षमता को साबित किया है। उनकी यह क्षमता ही उन्हें दुनिया भर की टी-20 लीगों में एक बहुमूल्य संपत्ति बनाती है। एलन पिछले दो मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) सत्र से सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लिए खेल रहे थे, यह टीम क्रिकेट विक्टोरिया के हाई-परफॉरमेंस डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जाती है, जो मेलबर्न स्टार्स का भी प्रबंधन करता है।

अभिषेक को रैना ने लाल गेंद क्रिकेट खेलने की सलाह दी

नई दिल्ली। भारतीय टी20 टीम के आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पिछले कुछ समय से अपनी लय में नहीं दिखे हैं। उनकी बल्लेबाजी की जो चमक शुरूआत में नजर आयी थी वह अब नहीं दिख रही।

निरंतरता की कमी से वे रैंकिंग में भी तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। इसी को देखते हुए पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने अभिषेक को समय मिलने पर लाल गेंद क्रिकेट खेलने की सलाह दी है।

गौरतलब है कि अभिषेक ने अपने करियर में कुल 206 टी20 मैचों में 32.40 की औसत से 5995 रन बनाए हैं, लेकिन जब बात प्रथम श्रेणी क्रिकेट की आती है, तो उनके आंकड़े उतने प्रभावशाली नहीं हैं। उन्होंने अपना आखिरी फर्स्ट-क्लास मैच 2024 में खेला था और अब तक खेले केवल 24 मैचों में एक शतक और पांच अर्धशतक सहित 30.60 की औसत से 1071 रन ही बना सके हैं। ये बल्लेबाज पिछले डेढ़ साल से लाल गेंद के क्रिकेट से दूर रहा है, ऐसे में रैना की टेस्ट क्रिकेट खेलने की सलाह कई सवाल खड़े करती है।

एक शो में रैना ने कहा कि क्रिकेट की मांग बदल गई है और अब अलग-अलग प्रारूपों के लिए अलग-अलग टीमें बनाई जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आज की पीढ़ी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। रैना ने सीधे तौर पर कहा, मुझे लगता है कि अभिषेक को टेस्ट खेलना चाहिए। उन्होंने कोचों द्वारा प्रतिभाओं को निखारने और मार्गदर्शन देने की भूमिका पर भी जोर दिया, साथ ही मानव सुथार जैसे युवा खिलाड़ियों का भी जिक्र किया कि क्या वे अगले रवींद्र जडेजा बन सकते हैं और तीनों प्रारूपों में खेलने के लिए तैयार हैं।

अभिषेक के लिए यह साल अब तक अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने 23 टी20 मैचों की इतनी ही पारियों में सिर्फ 23.36 की औसत से 514 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। अफगानिस्तान सीरीज में अब देखना है कि वह कैसा प्रदर्शन करते हैं।

13 सितंबर को एंजो फर्नांडीज मैनचेस्टर सिटी की ओर से प्रीमियर लीग में उतरेंगे

लंदन। अजेर्टीनी मिडफील्डर एंजो फर्नांडीज अब इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी की ओर से प्रीमियर लीग फुटबॉल में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। फर्नांडीज को हाल ही में मैनचेस्टर सिटी ने अनुबंधित किया है1 वह आगामी 13 सितंबर को होने वाले मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ उतरेंगे। इस मुकाबले को लेकर वह उत्साहित हैं। चेल्सी से मैनचेस्टर सिटी में शामिल हुए फर्नांडीज ने कहा कि वह अपने नए क्लब में बेहद खुश हैं और उसे अच्छी शुरूआत चाहते हैं।

नेहरा अभी गुजरात टाइटंस में ही रहेंगे

नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर और गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच आशीष नेहरा ने कहा है कि अभी वह आईपीएल में ही रहेंगे। नेहरा के अनुसार अगर भविष्य में उन्हें भारतीय टीम का कोच बनने का प्रस्ताव मिला तो वह उसपर विचार करेंगे। नेहरा के इस बयान से साफ है कि उनका पूरा ध्यान इस समय गुजरात टाइटंस के साथ अपनी मौजूदा भूमिका पर केंद्रित है।

हालांकि, नेहरा ने यह भी बताया कि अगर भविष्य में उन्हें भारतीय टीम को कोचिंग देने का प्रस्ताव मिलता है, तो वह इस फैसले पर परिवार से बात कर ही विचार करेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह राष्ट्रीय टीम के कोच की व्यस्तता और लगातार यात्रा करना है। नेहरा के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोच की भूमिका के लिए आठ से नौ महीने तक देश से बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले वह परिवार के साथ इसकी व्यावहारिकता पर विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि अंतरराष्ट्रीय कोचिंग में काफी यात्रा और कई प्रकार की चुनौतियां शामिल होती हैं।

हरा ने आईपीएल में बतौर कोच अपनी एक मजबूत पहचान स्थापित की है। गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच बनने के बाद उन्होंने टीम को पहले सत्र में ही विजेता बना दिया। 2022 में ही आईपीएल चैंपियन बनाया। इसके अगले सत्र में टीम उपविजेता रही। इस तरह नेहरा ने बतौर कोच अपने शुरूआती वर्षों में ही आईपीएल में अपनी रणनीतिक क्षमता और नेतृत्व कौशल को सिद्ध कर दिया है।

नेहरा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लंबे समय तक एक प्रभावी तेज गेंदबाज की भूमिका निभा चुके हैं। वह उस भारतीय टीम का भी हिस्सा थे, जिसने 2003 वनडे विश्व कप में उपविजेता के रूप में अपना अभियान समाप्त किया था। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कोचिंग में कदम रखा और गुजरात टाइटंस के साथ उनकी सफलता ने उन्हें आईपीएल के सबसे प्रमुख और सम्मानित कोचों में शामिल कर दिया है। उनके इन बयानों से फिलहाल यही निष्कर्ष निकलता है कि वह राष्ट्रीय टीम की कोचिंग को लेकर कोई सक्रिय योजना नहीं बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह गुजरात टाइटंस के साथ अपनी मौजूदा भूमिका में संतुष्ट और खुश हैं, पर अगर भविष्य में यदि टीम इंडिया की कोचिंग का कोई प्रस्ताव उनके सामने आता है, तो वह इसे सम्मान के साथ स्वीकार करने की संभावना पर परिवार के साथ विचार करेंगे।

प्रीमियर लीग फुटबॉल में होगी पेड्रो की असली परीक्षा

लंदन। ब्राजील के स्टार फॉरवर्ड जोआओ पेड्रो साल 2034 तक चेल्सी में ही रहेंगे। ऐसे में उनका लक्ष्य अब क्लब को अधिक से अधिक सफलता दिलाना है। उनकी असली परीक्षा 13 सितंबर से शुरू हो रही प्रीमियर लीग फुटबॉल में होगी। इसमें देखना होगा कि पेड्रो चेल्सी के लिए कितने फायदेमंद होते हैं। इस फॉरवर्ड ने जुलाई 2025 में ब्राइटन एंड होव एल्बियन को छोड़कर चेल्सी में प्रवेश किया था। उन्होंने क्लब को फीफा क्लब विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। पेड्रो ने सेमीफाइनल में अपने पूर्व क्लब फ्लुमिनेंस के खिलाफ दो शानदार गोल किए थे और फिर पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) के खिलाफ हुए फाइनल में भी गोल किया था।

चेल्सी में अपने पहले पूरे सत्र में पेड्रो ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में कुल 20 गोल किये, जिसके चलते उन्हें समर्थकों द्वारा क्लब का प्लेयर ऑफ द सत्र चुना गया। उन्होंने 2025/26 सत्र में चेल्सी का पहला गोल वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ एक अवे गेम में किया था। इसके बाद उन्होंने टोटेनहम हॉटस्पर के खिलाफ भी जीत दर्ज की थी। यूईएफए चैंपियंस लीग में भी उन्होंने नेपोली के खिलाफ चेल्सी की जीत में दो गोल किए। अपने कार्यकाल को बढ़ाने के बाद जोआओ पेड्रो ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं चेल्सी के साथ करार बढ़ाकर बेहद उत्साहित हूँ। मैंने हमेशा एक बड़े क्लब के लिए खेलने का सपना देखा था, और इस क्लब के प्रति अपनी लंबी अवधि की प्रतिबद्धता जताना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।

इंदौर संभाग ने जीती 70वीं राज्य स्तरीय शालेय शूटिंग चैंपियनशिप

इंदौर। 70वीं राज्य स्तरीय शालेय शूटिंग प्रतियोगिता में इंदौर संभाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की। इंदौर के खिलाड़ियों ने 28 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 44 पदक जीते। पांच दिवसीय प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल, राऊ में हुआ।

राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता के तहत 7 से 11 सितंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, जनजातीय विभाग, नर्मदापुरम, सागर, रीवा और उज्जैन संभागों के करीब 375 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने विभिन्न निशानेबाजी स्पधाओं में भाग लिया।

कई स्पधाओं में इंदौर का दबदबा

बालक वर्ग की ओपन साइट स्पर्धा में इंदौर संभाग प्रथम रहा। सागर और उज्जैन ने दूसरा तथा भोपाल और जबलपुर ने तीसरा स्थान हासिल किया। पीप साइट की 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की बालक-बालिका स्पधाओं में भी इंदौर संभाग ने पहला स्थान प्राप्त किया।

एयर पिस्टल की विभिन्न आयु वर्ग की स्पधाओं में भी इंदौर के खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावी रहा। व्यक्तिगत स्पर्धा में अंडर-19 बालक एयर पिस्टल में इंदौर के कविश ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं अंडर-19 बालिका पीप साइट में इंदौर की अश्विनी मुजाल्दे ने स्वर्ण पदक जीता।

समापन पर खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत

प्रतियोगिता का समापन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर संभाग अनीता चौहान के मुख्य आतिथ्य में हुआ। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्हें खेलों में निरंतर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। पुरस्कार वितरण संयुक्त संचालक अनीता चौहान, संभागीय खेल अधिकारी हेमंत वर्मा और एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल के वरिष्ठ पीटीआई अकरम खान ने किया।

चोर स्टार्ट नहीं कर पाएंगी गाड़ी, कनेक्टड कारों के लिए आया रिमोट इमोबिलाइजर

गुरुग्राम। हुंडई मोटर इंडिया (एचएमआईएल) ने अपनी कारों में एक और सुरक्षा फीचर जोड़ते हुए रिमोट इमोबिलाइजर पेश किया है जिससे वाहन को अनाधिकृत रूप से स्टार्ट करने से रोका जा सकेगा।

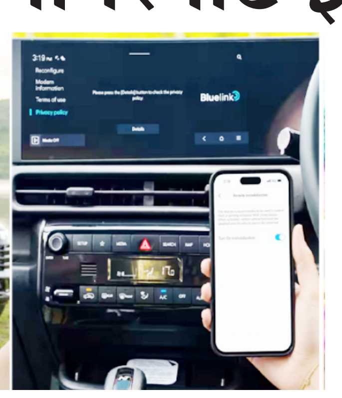

कंपनी ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि हुंडई वेन्यू के एचएक्स10 और हुंडई वेन्यू एन लाइन के एन10 संस्करण में अभी यह फीचर पेश किया जा रहा है। इन दोनों संस्करणों में कनेक्टेड-कार-नेविगेशन-कॉकपिट लगा हुआ है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से हुंडई ब्लूलिंक से लैस सभी वाहनों में यह अपडेट उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही भविष्य में आने वाली कंपनी की सभी कनेक्टेड कारों में यह एक मानक फीचर होगा।

वाहन मालिक हुंडई ब्लूलिंक ऐप के जरिए अपनी पार्क की गई कार को दूर से ही इमोबिलाइज कर सकेंगे यानी उसे स्टार्ट होने से रोक सकेंगे। यह न सिर्फ चोरी या लूट की स्थिति में काम आयेगा, बल्कि नाबालिग बच्चों को भी बिना अनुमति कार ले जाने से रोकने में कारगर होगा। यदि चोरी का शक हो, तो ग्राहक हुंडई ब्लूलिंक ऐप के जरिये तुरंत इस फीचर को सक्रिय कर सकते हैं, ताकि गाड़ी बंद होने के बाद उसे दोबारा स्टार्ट न किया जा सके। इसके अलावा, नेटवर्क कनेक्टिविटी होने पर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा ग्राहकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गाड़ी का पता लगाने में मदद कर सकती है। यह फीचर चलती हुई गाड़ी को रोकता या बंद नहीं करता है। ग्राहक चोरी रोकने के लिए पार्क करते समय ही ब्लूलिंक ऐप से इमोबिलाइजर चालू कर सकते हैं। चोरी के शक की स्थिति में रिएक्टिव इमोबिलाइजेशन का विकल्प होता है, जिससे एक बार बंद होने के बाद कार को दोबारा चालू नहीं किया जा सकेगा।

59 बिजली संयंत्रों में सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा

नई दिल्ली। देश के ऊर्जा क्षेत्र के सामने फिर संकट खड़ा हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के लगभग एक तिहाई कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में ईंधन का भंडार खतरनाक स्तर तक घट गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के ताजा आंकड़ों के अनुसार, ऐसे बिजली संयंत्र जहां कोयले का भंडार कुल जरूरत का 25 फीसदी से भी कम बचा है यानी जिनके पास मात्र 3 दिन का कोयला शेष है उनकी संख्या 9 सितंबर तक 59 हो गई है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के विश्लेषक मनोज कुमार का कहना है कि घटता कोयला भंडार ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चेतावनी है। मई में देश की बिजली की अधिकतम मांग 270.70 गीगावॉट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार 267 गीगावॉट के आसपास बनी हुई है।

आरबीआई ने अतिरिक्त नकदी खींचने के लिए की 1 लाख करोड़ रुपए के ओएमओ बॉन्ड की बिक्री की घोषणा

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग प्रणाली में मौजूद अतिरिक्त नकदी को अवशोषित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्डों की ओपन मार्केट सेल (ओएमओ) की घोषणा की है. केंद्रीय बैंक वित्त वर्ष 2028-29 से 2031-32 के बीच परिपक्व होने वाले बॉन्डों की बिक्री करेगा. यह कदम वित्तीय प्रणाली में बढ़ी हुई तरलता को नियंत्रित करने और अल्पकालिक ब्याज दरों को नीतिगत स्तर के करीब बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.

आरबीआई के अनुसार, बॉन्ड बिक्री तीन चरणों में की जाएगी. पहले चरण में 17 सितंबर 2026 को 50,000 करोड़ रुपए, दूसरे चरण में 21 सितंबर 2026 को 25,000 करोड़ रुपए और तीसरे चरण में 28 सितंबर 2026 को 25,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचे जाएंगे. यह नीलामी बहु-प्रतिभूति (मल्टी-सिक्योरिटी) और बहु-मूल्य (मल्टीपल प्राइस) पद्धति के तहत आयोजित की जाएगी.

यह पिछले दो वर्षों में आरबीआई द्वारा की जा रही पहली शुद्ध ओपन मार्केट बॉन्ड बिक्री होगी. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने सितंबर 2024 में द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की थी. वहीं वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान आरबीआई ने एक साथ बॉन्ड खरीद और बिक्री की रणनीति अपनाई थी. केंद्रीय बैंक ने कहा कि पात्र प्रतिभागियों को 17 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से अपनी बोलियां जमा करनी होंगी. नीलामी के नतीजों की घोषणा उसी दिन की जाएगी. आरबीआई की घोषणा के बाद सरकारी बॉन्ड बाजार में दबाव देखने को मिला. बॉन्ड बिकवाली की खबर के बाद प्रतिफल (यील्ड) में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई और वे तीन महीने से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए. देश के मानक 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की यील्ड 6 आधार अंक बढ़कर 7.035 प्रतिशत हो गई, जबकि 5 वर्षीय बॉन्ड की यील्ड लगभग 10 आधार अंक बढ़कर 6.6222 प्रतिशत तक पहुंच गई. भारतीय बैंकिंग प्रणाली इस समय अतिरिक्त नकदी की स्थिति का सामना कर रही है. हाल ही में बैंकों ने आरबीआई की विशेष विदेशी मुद्रा जुटाव योजना के तहत अपेक्षा से कहीं अधिक धन जुटाया, जिसके चलते देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में रुपए की तरलता बढ़ गई है. अतिरिक्त नकदी के कारण रातोंरात (ओवरनाइट) ब्याज दरें आरबीआई की रेपो रेट से नीचे आ गई हैं. ऐसे में केंद्रीय बैंक के लिए तरलता को नियंत्रित करने वाले कदम उठाना आवश्यक हो गया है. यह स्थिति ऐसे समय बनी है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है, जिससे महंगाई पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका बनी हुई है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आरबीआई अतिरिक्त तरलता को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के उपायों का उपयोग कर सकता है, जिनमें विदेशी मुद्रा स्वैप, मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम (एमएसएस) बॉन्ड, ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में संभावित बढ़ोतरी जैसे कदम शामिल माने जा रहे थे.

केंद्र सरकार ने राज्यों से श्रमिक कल्याण के लिए सेस निधि का प्रभावी उपयोग करने का किया आग्रह

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे श्रमिक कल्याण के लिए एकत्र किए गए सेस फंड के उपयोग की विस्तृत समीक्षा करें, कमियों की पहचान करें और श्रमिकों के दीर्घकालिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके प्रभावी इस्तेमाल के नए उपाय तलाशें.

मुंबई में आयोजित भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने राज्यों से श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) के लागू होने के एक वर्ष बाद उनके प्रभाव का व्यापक आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने को भी कहा, जहां बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है. उन्होंने श्रम कानूनों से जुड़े पेशेवरों के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे श्रम संहिताओं को सही मायनों में प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी. मंडाविया ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह योजना रोजगार को बढ़ावा देने और कार्यबल में शामिल होने वाले नए लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने राज्य सरकारों से उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के साथ विशेष कार्यशालाएं और संवाद कार्यक्रम

आयोजित करने का आग्रह किया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना की जानकारी मिल सके और पात्र लाभार्थी इसका लाभ उठा सकें.

मंत्री ने राज्यों के बीच सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान और बीओसीडब्ल्यू फंड के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि इससे श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ श्रम तंत्र को भी लगातार विकसित होने की जरूरत है और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के समग्र कल्याण के लिए केंद्र और राज्यों की सोच तथा नीतियों में तालमेल होना चाहिए. मांडविया ने श्रमिकों को अधिक सम्मान, गरिमा और आत्मसम्मान देने के उपायों पर भी बल दिया. उन्होंने श्रमिकों के लिए पेंशन सहायता प्रदान करने की संभावना पर विचार करने की आवश्यकता जताई. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की मांग बढ़ रही है, इसलिए भारत के कार्यबल को इन अवसरों के अनुरूप तैयार करना जरूरी है.

केंद्रीय मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय श्रम गतिशीलता (इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी) पर भी चर्चा की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि इससे देश को प्रेषण (रेमिटेंस) के रूप में आर्थिक लाभ मिलेगा और भारत की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को भी पूरा किया जा सकेगा. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से समन्वित प्रयासों के जरिए अंतरराष्ट्रीय श्रम गतिशीलता के लिए एक व्यापक मंच विकसित करने का आह्वान किया, जिसमें आवश्यक वित्तीय और डिजिटल ढांचा भी उपलब्ध हो, ताकि भारतीय श्रमिक वैश्विक अवसरों का लाभ उठा सकें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता और मजबूत हो.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रम एवं रोजगार सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने कहा कि देश में निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों की संख्या 7 करोड़ से अधिक है. उन्होंने बताया कि देशभर में बीओसीडब्ल्यू सेस फंड के रूप में करीब 77,000 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन राज्यों के बीच बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करने और उद्योग जगत के साथ विचार-विमर्श करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है.

मध्य प्रदेश के डबरा में स्कूल बस ड्राइवर पर फायरिंग

घटना के वक्त 50 बच्चे थे सवार : एसडीओपी मौके पर, बस थाने में खड़ी

ग्वालियर/डबरा

पिछोर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब स्कूली बच्चों से भरी बस को भी नहीं बख्शा। शनिवार तड़के टेकनपुर के ग्लोरीयस कॉन्वेंट स्कूल की बस ड्राइवर पर कार सवार दो युवकों ने कट्टे से 4 राउंड फायरिंग कर दी। घटना के समय बस में करीब 50 बच्चे सवार थे। फायरिंग में बस चालक खेम सिंह घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना में पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है।

जानकारी के अनुसार बस सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। बड़ी अकबई गांव के पास सड़क पर एक स्विफ्ट कार बीच में खड़ी थी। कार पर 'गुर्जर' लिखा था और काले शीशे लगे थे। ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर कार हटाने को कहा तो युवकों ने पेट्रोल खत्म होने का बहाना बनाया।

ड्राइवर ने धक्का देकर कार हटाने की बात कही तो दोनों आरोपी भड़क गए और ड्राइवर से उलझ पड़े। बहस के दौरान ही एक आरोपी ने अवैध कट्टा निकालकर बस पर ताबड़तोड़ 4 फायर झोंक दिए। बताया जा रहा है कि गोली ड्राइवर को लगी।

शुरू कर दी है तलाश

घटना की सूचना पर एसडीओपी सौरभ कुमार और पिछोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस को थाने परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया और बच्चों को सुरक्षित परिजनों के हवाले किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

बंडा में जहरीली शराब का कहर जारी

सागर। जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुडारी बुजुर्ग में पदस्थ पंचायत सचिव अजय लोधी (30) की शुक्रवार को बीएमसी सागर में उपचार के दौरान मौत हो गई। अजय स्वर्गीय गनपत सिंह लोधी के पुत्र थे। जहरीली शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें उपचार के लिए बीएमसी में भर्ती कराया गया था।

परिजनों के मुताबिक अजय के पिता की मृत्यु के बाद कुछ वर्ष पहले ही उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। उनकी मौत के बाद जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 33 हो गई है। वहीं करीब एक दर्जन लोग अभी बीएमसी के आईसीयू में उपचाररत हैं।

जहरीली शराब को पीने के बाद 5 सितंबर से जहरीली शराब से प्रभावितों को बीएमसी में भर्ती कराया जा रहा है। तब से लेकर अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया, जब किसी की मौत नहीं हुई हो। अब तक 33 लोग की मौत इस जहरीली शराब से हो चुकी है। जहरीली शराब पीकर मरने वाले लोगों में 25 से 38 साल के नौजवानों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं एक महिला की भी मौत इस जहरीली शराब से हुई है।

इलाज के दौरान पंचायत सचिव ने तोड़ा दम, मृतकों का संख्या 33 पहुंची

पुलिस की कार्रवाई जारी

जहरीली शराब प्रकरण में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अवैध शराब बनाने और बेचने में शामिल आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई के साथ उनके मकानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। सरकारी जमीन से कब्जे हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। उधर शराब बनाने का कथित फामूर्ला उपलब्ध कराने के आरोपी रवि लखेरा को पुलिस ने शुक्रवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। उसे उपचार के लिए बीएमसी में भर्ती कराया गया है।

भोपाल में मेट्रो रूट पर टीडीआर लागू करने का विरोध

लोग बोले- पहले नक्शा दिखाओ

भोपाल। भोपाल मेट्रो रेल कॉरिडोर के दोनों किनारों पर लगभग आधा किलोमीटर क्षेत्र को ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) प्राप्ति क्षेत्र घोषित करने की सरकारी कवायद पर विवाद खड़ा हो गया है। संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) द्वारा आमंत्रित दावे-आपत्तियों के बीच संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव की वैधानिकता, पारदर्शिता और औचित्य पर विरोध दर्ज कराया।

समिति के प्रतिनिधि विवेक त्रिपाठी और लवनीश भाटी ने विभाग को औपचारिक आपत्ति सौंपते हुए कहा कि विभागीय दफ्तर अथवा वेबसाइट पर टीडीआर क्षेत्र का विस्तृत नक्शा, प्रभावित खसरा नंबर और निर्माण मापदंड सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ऐसे में आम नागरिक किस आधार पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं।

समिति ने सवाल किया कि जब शासन भोपाल विकास योजना-2047 तैयार करने की घोषणा कर चुका है, तब दो दशक पुराने मास्टर प्लान-2005 में इतना बड़ा फेरबदल करने का क्या औचित्य है। मेट्रो कारिडोर के दायरे में श्यामला हिल्स, अरेरा कालोनी ई-1 से ई-5, बड़े तालाब का कैचमेंट, संरक्षित वन व राजभवन जैसे संवेदनशील क्षेत्र आते हैं। टीडीआर लागू होने से निर्माण घनत्व बढ़ेगा, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और यातायात पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा।

शामिल करने की रखी मांग

समिति ने मांग की है कि संबंधित क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन और पर्यावरण प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट पहले सार्वजनिक की जाए। साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 के तहत राजपत्र में अनिवार्य प्रकाशन की प्रक्रिया जांची जाए। समिति ने 2005 के प्लान में इस संशोधन को तुरंत निरस्त कर इसे आगामी मास्टर प्लान-2047 में सार्वजनिक परामर्श के बाद ही शामिल करने की मांग रखी है।

मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तीव्र गति से करें - मुख्य सचिव श्री बर्णवाल

भोपाल। बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां भी करवाई जाये। मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जाए एवं समय-सीमा में काम पूर्ण किया जाए। उक्त निर्देश मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 अंतर्गत आज मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल ने निमार्णाधीन मेडिकल कॉलेज धार के निरीक्षण के दौरान दिये। उनके साथ सचिव, मुख्यमंत्री डॉ. सुदाम खाडे भी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने धार जिला मुख्यालय पर संचालित कन्या आवासीय परिसर के निरीक्षण के दौरान अध्ययनरत बालिकाओं से आत्मीय संवाद कर उनकी पढ़ाई, परिसर में संचालित गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं के संबंध में जानकारी ली।

हत्या के आरोपी गुंडों ने नेता के संरक्षण में थाने में किया सरेंडर

एक आरोपी सूरज की तलाश में पुलिस मार रही छापे

इंदौर। गाय चोरी के आरोप में युवक को पीट-पीट कर मारने वाले गुंडों को विधायक समर्थकों का संरक्षण मिल रहा था। वारदात के बाद विधायक के इशारे पर थाने में सरेंडर कराया गया है। पूछताछ में कथित तौर पर हिंदू संगठन से जुड़े नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। कुछेक तो लव जिहाद और गौ तस्करी की आड़ में अवैध वसूली करते हैं।

देवास नाका निवासी चंदर लोहार की तलावली चांदा निवासी सूरज जाट और भुरू यादव की गैंग ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। चंदर पर भुरू की गाय चुराने का आरोप लगाया गया था। उसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। लसूड़िया पुलिस ने गुरुवार रात भुरू यादव और कुणाल यादव (नंदा नगर) की गिरफ्तारी दर्शा दी। पुलिस ने मुखबिर और मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार करने का दावा किया है।

जबकि कुणाल भाजपा नेताओं से जुड़ा है। भाजपा विधायक और उनके समर्थकों का संरक्षण है। दबाव बनाने पर उसे अंकित यादव ने सरेंडर करवाया है। अंकित का रिश्तेदार बिट्टू भी वारदात में बताया जा रहा है। उधर पुलिस सूरज की तलाश में दबिश दे रही है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है। पुलिस ने सूरज की पत्नी को हिरासत में ले लिया है।

सूरज जाट के बारे में पता चला कि वह शराब ठेकेदारों से जुड़ा है। एमआर-10, लसूड़िया, कनाड़िया, पलासिया क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालों को धमका कर उनसे रुपये वसूलता है। सूरज ने करीब 100 युवकों की गैंग बना ली है। ठेकेदार से शराब न खरीदने वालों को अगवा तक कर लेता है।

पातालपानी हेरिटेज स्टेशन की बिजली गुल, 8 लाख का बिल बकाया

वेटिंग रूम-वॉशरूम से अनाउंसमेंट सिस्टम तक ठप

पातालपानी। चर्चित हेरिटेज ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को पातालपानी स्टेशन पर इन दिनों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 8 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया होने के कारण विद्युत वितरण कंपनी ने स्टेशन का कनेक्शन काट दिया है। पिछले तीन दिनों से स्टेशन की बिजली सप्लाई बंद है और पूरा काम जनरेटर के सहारे चल रहा है।

वेटिंग रूम और वॉशरूम में अंधेरा

हेरिटेज ट्रेन का संचालन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होता है। शुक्रवार को ट्रेन का संचालन हुआ, लेकिन स्टेशन पर बिजली नहीं होने से यात्रियों को असुविधा हुई। वेटिंग रूम और वॉशरूम में अंधेरा छाया रहा। शाम और रात के समय स्थिति और मुश्किल हो जाती है। अंधेरे के कारण स्टेशन की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। डीजल और अन्य सामग्री की चोरी की आशंका भी बनी हुई है।

अनाउंसमेंट सिस्टम भी बंद

बिजली कनेक्शन कटने के कारण स्टेशन का अनाउंसमेंट सिस्टम पूरी तरह बंद है। शाम के समय हेरिटेज ट्रेन के डिब्बों में पानी भरने के लिए भी रेलवे को जनरेटर चलाना पड़ा। इससे स्टेशन की नियमित व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं।

नोटिस के बाद काटा कनेक्शन

विद्युत वितरण कंपनी के सहायक अभियंता जयेश शुक्ला ने बताया कि पातालपानी स्टेशन का करीब 8 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। जून में भी कनेक्शन काटा गया था। भुगतान नहीं होने पर नोटिस दिया गया और इसके बाद दोबारा बिजली कनेक्शन काट दिया गया।

वार्ड 24 से पार्षद जीतू यादव की एमआईसी में वापसी

अमेरिका रवाना होने से पहले महापौर ने जारी किया पत्र

इंदौर। वार्ड 24 से पार्षद जीतू यादव की महापौर परिषद (एमआईसी) में वापसी हो गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को अमेरिका रवाना होने से पहले इस संबंध में पत्र जारी कर दिया। पत्र जारी होते ही नगर निगम और भाजपा गलियारों में चर्चा शुरू हो गई।

जीतू यादव को भाजपा के एक अन्य पार्षद कमलेश कालरा के नाबालिग बेटे के साथ घर में घुसकर मारपीट और अभद्रता के मामले में नाम सामने आने के बाद पार्टी से बाहर कर दिया गया था। इसके साथ ही उनकी एमआईसी भी छीन ली गई थी। यादव करीब 18 महीने तक पार्टी से बाहर रहे। इस पूरे मामले में पुलिस ने कोर्ट में पेश पूरक चालान में जीतू यादव को क्लीन चिट दे दी। चालान में कहा गया कि घटना में यादव की संलिप्तता के कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। पुलिस रिपोर्ट के बाद भाजपा संगठन ने भी यादव का 'वनवास' खत्म करते हुए उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया था।

संगठन ने वापसी पर मुहर लगा दी

पार्टी में वापसी के बाद से ही उनके एमआईसी लौटने की चर्चा चल रही थी। इसे लेकर भाजपा के भीतर विरोध के स्वर भी उठे, लेकिन अंततः संगठन ने उनकी वापसी पर मुहर लगा दी। सूत्रों के अनुसार, यादव को लेकर कुछ नेता और विधायक भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मिले थे। इन नेताओं ने यादव के खिलाफ हुई शिकायत और पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष रखा। संगठन के सामने मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही जीतू की वापसी का रास्ता साफ हुआ।

यह था मामला

जनवरी 2025 में भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के घर हुए हंगामे और नाबालिग बेटे के साथ मारपीट के बाद जीतू यादव का नाम विवाद में आया था। इसके बाद संगठन ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। करीब 18 महीने बाद पुलिस जांच में राहत मिलने और पार्टी में वापसी के बाद अब उन्हें फिर से एमआइसी में जगह मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की काले हिरण और चिंकारा के शिकारी और तस्कर की जमानत याचिका

भोपाल। प्रदेश में काले हिरण एवं चिंकारा के अवैध शिकार तथा उनके मांस की तस्करी के मुख्य आरोपी सबाह अंतुले की जमानत याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली की युगल पीठ ने खारिज कर दिया है। एसटीएसएफ इंदौर इकाई, स्थानीय पुलिस और वनमंडल इंदौर की संयुक्त टीम ने किशनगंज में की गई कार्रवाई के दौरान लगभग 65 किलोग्राम वन्यजीव मांस, एक देशी पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और तस्करी में प्रयुक्त टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन जब्त कर तीन आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई जारी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सागर जिले में कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शाहगढ़ के ग्राम सिमरिया उवरी में प्रशासन और राजस्व टीम ने कार्रवाई करते हुए बंडा अवैध शराब मामले के आरोपी चंद्रभान राजपूत द्वारा कब्जा की गई 4.79 हेक्टेयर शासकीय भूमि को मुक्त करा लिया है। जांच के दौरान यह बात उजागर हुई थी कि बंडा प्रकरण में संलिप्त आरोपी चंद्रभान राजपूत ने ग्राम सिमरिया उवरी में ग्राम चौकीदार की शासकीय सेवा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्य खेल मंत्री श्री मांडविया से की सौजन्य भेंट

मध्यप्रदेश के विकास, रोजगार और युवाओं से जुड़े विषयों पर हुई सार्थक चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया से सौजन्य भेंट की। इस अवसरपर मध्यप्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, युवाओं के कौशल विकास तथा प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों के विस्तार से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही प्रदेश के युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से रोजगार एवं कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया।

महत्वपूर्ण विषयों पर भी होगी चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया के बीच युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के विस्तार, कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा केंद्र और राज्य के समन्वय से रोजगारपरक गतिविधियों को गति देने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया तकनीक, नवाचार और नवीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर केन्द्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ

परिवहन व्यवस्था को आधुनिक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट-2026 के दौरान तकनीक, नवाचार और प्रदेश के नवीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

साथ ही उन्होंने ब्रिलियंट कन्वेशन सेंटर में ही ₹यात्री परिवहन विजन समिट-2026₹ में बस निमार्ताओं, आईटी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य उद्योगों के साथ प्रदेश के विभिन्न शासकीय निगमों की गतिविधियों और नवाचारों पर आधारित इंडस्ट्री एक्सपो का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक्सपो में विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदर्शित बसों का अवलोकन किया तथा उनके फीचर्स और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं की जानकारी ली।

प्रदर्शनी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित, आधुनिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई कंपनियों और संस्थानों ने सहभागिता की। प्रदर्शनी में कंपनियों ने अपनी तकनीक, सेवाओं, उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त उन ईवी बसों को भी प्रदर्शित किया गया, जो भविष्य में परिवहन का अहम जरिया बनेंगी।

एसबीआई-इंडियन ऑयल सहित कई कंपनियों ने लिया हिस्सा

प्रदर्शनी में थिंक गैस, यश टेक्नोलॉजीज, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), इंडियन ऑयल, लाइट मेट्रिक्स, एमपीआईडीसी, क्यूब कंस्ट्रक्शन, कल्याणी पावरट्रेन लिमिटेड और ओम्निफिसेंट सहित विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में परिवहन क्षेत्र से जुड़े आधुनिक समाधानों, तकनीकी नवाचारों, ऊर्जा और ईंधन से संबंधित सुविधाओं तथा अधोसंरचना विकास की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान परिवहन एवं स्कूलशिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित थे।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।